ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

नागवंश की धरोहर है नवरतन गढ़

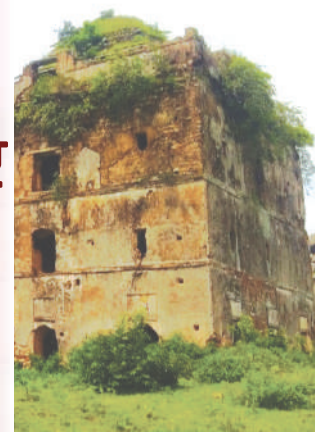

रविवारीय, 12 - 18 जुलाई 2020 वर्ष- एक, अंक-49, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेंट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं ह्वाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

झारखण्डवासियों से मेरी अपील घर पर रहें, सुरक्षित रहें : हेमन्त सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। मुख्यमंत्री ने कहा झारखण्डवासियों से मेरी अपील है कि सुरक्षित रहें। अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। सभी के सहयोग से हम कोरोना को हरायेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।

सभी का स्वाब सैंपल जांच के लिए लिया गया :मंत्री मिथलेश ठाकुर और विधायक मथुरा महतो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन व मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत सभी पदाधिकारियों व कर्मियों का तीन डॉक्टरों की टीम ने स्वाब सैंपल जांच के लिए लिया है। प्रथम चरण के जांच में मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है।

12 जुलाई को वि.वि. के 60वें स्थापना दिवस पर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, आरयू के छात्रों की भेजी गयी विशेष स्टोरी

रांची विश्वविद्यालय का मोराबादी परिसर:रमणिक और सुकूनदेह

रांची पहाड़ी मंदिर के शिखर पर चढ़कर जब हम समूचे रांची का अवलोकन करते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर एक हरियाली की चादर सी नजर आती है और उस हरियाली के बीच में गिने चुने भवन नजर आते हैं। दरअसल शहरी रांची का यह इलाका राजभवन के उद्यान और रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी परिसर के कारण इतनी हरियाली लिये हुये दिखता है। आपाधापी और व्यस्त जिंदगी के कारण हम रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी कैंपस की रमणिकता और खुबसूरती को नजरअंदाज कर जाते हैं, पर शोरगुल, ट्रैफिक और प्रदूषण से मुक्त यह परिसर बहुत ही सुकूनदेह और रमणिक है।

1960 में स्थापित रांची विश्विद्यालय का 12 जुलाई को 60वां स्थापना दिवस भी है । किसी भी शैक्षणिक परिसर के लिये आदर्श वातावरण की कसौटी को रांची विश्वविद्यालय का मोराबादी कैंपस पूरा करता है। कुछ साल पहले रांची कॉलेज के सामने के बड़े मैदान में विश्वविद्यालय के पीजी विज्ञान विषयों का भव्य भवन बनाया गया, इसी में आज रांची विवि का रेडियो खांची और आर्यभट्ट सभागार भी है, लेकिन इसमें इस बात का विशेष खयाल रखा गया कि इससे यहां की खुबसूरती या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। यही कारण है कि बेसिक साइंस परिसर के बनने के बाद भी इसमें बॉटनिकल गार्डन का निर्माण किया गया जिसमें कई प्रकार के दुर्लभ पेड़ पौधे लगाये गये हैं। इस सुनियोजित प्रयास के कारण से ही विशाल भवनों के बनने के बावजूद परिसर पर्यावरण अनुकूल हरियाली लिये हुये सुंदर दिखता है। ऐसा यहां के प्राध्यापकों छात्रों के निजी लगाव और इसे सुंदर बनाने के प्रयास के कारण संभव हुआ है।

फोटोः राकेश कुमार दास

पर्यावरण प्रेमी है कुलपति डॉ. रमेश कु. पांडेय

वर्तमान कुलपति डॉ. रमेश कुमार पांडेय बॉटनी के प्राध्यापक हैं और स्वयं इनका समर्पण हरियाली , बाग बगीचों और परिसर को स्वच्छ रखने में रहता है। इन्होंने अपने पहले कार्यकाल में ही पूरे मोराबादी कैंपस के प्रत्येक विभागों में खाली पड़े जगहों को साफ करवा कर वहां तरह तरह के पेड़ पौधे लगवा दिये। यही कारण है कि कुछ ही सालों में प्रत्येक विभाग एक रमणिक और शांत शैक्षणिक परिसर में बदल गया। कुलपति का जुनून कुछ ऐसा है कि वह स्वयं पेड़ पौधे लेकर परिसर को सजाने संवारने में लग जाते हैं और विश्वविद्यालय के छात्रों प्राध्यापकों की टीम के साथ परिसर की साफ सफाई का आयोजन करते हैं।

तनावमुक्त कर देता है यहां के सेमल वृक्षों की छांव

पीजी आर्ट ब्लॉक परिसर में कतार में कई विशाल सेमल के पेड़ हैं निकी हरियाली और छांव किसी भी व्यक्ति को तनावमुक्त कर देता है। इस परिसर में गुलाब का एक बगीचा भी बनाया गया है जिसमें रंग बिरंगे गुलाब लगे हुये हैं। कमाल की बात है कि कुछ साल पहले यह परिसर बरसात में कीचड़युक्त हो जाता था और इसमें गिरने पड़ने के वाकये होते रहते थे। एक बार इससे खिन्न होकर छात्रों ने यहां धान रोप दिया था, लेकिन उसके बाद एकाएक ही पूरे परिसर की रौनक ही बदल गयी। सुव्यस्थित तरीके से इसमें टाइल्स लगा कर चारो ओर बाग बगीचे पेड़ पौधे लगाये गये जिससे यह परिसर अब बहुत ही रमणिक दिखता है। अब यहां छात्रों और अध्यापकों के वाहन पार्किंग के लिये भी पर्याप्त जगह बन गया है। वहीं बहुद्देशीय परीक्षा भवन अगर कोई आये तो उसे यहां दर्जनों किस्म के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों वाली लतायें देखने को मिलेंगी। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो अमूमन हमें कहीं और देखने को नहीं मिलतीं। इस परिसर में जंगल जलेबी के पेड़ भी दिख जायेंगे जो एक प्रकार का मीठा जंगली फल है जो गर्मियों में पकता है।

प्रचुर बारिश तब जल संकट क्यों?

शहरी संदर्भ में पानी की बचत का मतलब मूल रूप से, नल से अनावश्यक रूप से पानी को न बहने देना या लीक हो रहे नल को ठीक करने तक ही सीमित होकर रह जाता है। लेकिन कुछ बंद नल संकट के इस बहाव को नहीं रोक सकते। 2018 में नीति आयोग द्वारा किए गए अध्ययन में यह पुष्टि की गई कि भारत पानी के संकट से घिरा हुआ है, और 2030 पहुँचते हमें पानी का अकाल झेलना पड़ सकता है। इस धूमिल जलविहीन भविष्य से बचने के लिए जल संरक्षण के प्रयासों को कई स्तर पर करने की जरूरत है।

बारिश का पानी हमारा तारणहार हो सकता है

वर्षा जल का संग्रहण दो प्रकार से होता है। एक जिससे हम सब परिचित हैं और जो काफी जटिल लगता है। बारिश के पानी को जमीन में बनाए गए टैंक में जमा करना लेकिन जल संग्रहण एक और तरीके से पूर्ण होता है जिसे प्र-कृति अपने दम पर पूरा करती है, वह है भूजल पुनर्भरण। जब जीवन देने वाली बारिश जमीन पर गिरती है, तो यह जमीन की गहरी परत में सोख ली जाती है।और जब यह चट्टान की एक अभेद्य परत से मिलती है, तो यह भूजल जलाशय के रूप में एकत्रित होती है।

पानी की खपत की भरपाई के लिए हमें वर्षा जल के माध्यम से भूमिगत जल पुनर्भरण की आवश्यकता है। विकास और बड़े पैमाने पर शहरीकरण के कारण पेड़ कम हैं और बारिश भी कम होती है, इसलिए पहले की तुलना में भूमिगत जल को फिर से भरने के लिए बहुत कम पानी उपलब्ध है। और जो थोड़ी बारिश होती है, जमीन उसे सोख नही पाती क्योकि हमने हर क्षेत्र को सीमेंट में ढक रखा है।इसीलिए अधिकांश वर्षा जल नालों में बहता है जो कि पहले से ही कचड़ो के कारण अवरुद्ध हैं, और पानी का बहाव रुकने पर वह पानी रास्तों पर बहता है। और नतीजतन हमें बाढ़ और सूखे की परिस्थिति एक साथ झेलनी पड़ती है। 'आधुनिकीकरण', 'शहरीकरण', 'प्रगति', 'सौंदर्यीकरण' और 'विकास' के नाम पर व्यापक और सभी व्यापक कंक्रीट टाइल इस सरल प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित करती है। भूजल पुनर्भरण के लिए एकमात्र खाली जमीन, बस पार्क और निजी गार्डन तक ही सीमित हो रही है। झीलों, तालाबों और कई भूजल स्रोत शहरीकरण की मार झेल रहे हैं। कई स्रोत देखरेख के अभाव में है और दूसरी ओर कई छोटे तालाब आदि को भरकर बिल्डिंग्स खड़े कर दिए जा रहे हैं जिसका नतीजा यह है कि जल जमाव की जगह न होने पर वर्षा का पानी रास्तों पर बाढ़ का स्वरूप ले लेता है। हमारे घर के चारों ओर की ग्रीन बेल्ट को अब 'स्वच्छता' और 'सौंदर्यीकरण' की आड़ में सीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें केवल 'हरियाली' के नाम पर कुछ गमले में डाले पौधे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हम अपने ड्राइववे, गार्डन या जो भी अतिरिक्त जगह है इसे ठोस मुक्त रहने दें ताकि बारिश जमीन की गहरी परतों तक पहुँच धरती की प्यास बुझा सके। ● *ज्योति कुमारी*

तिल की खेती से दुगुनी होगी किसानों की आय

डॉ। सोहन राम

बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) के सौजन्य से संचालित अखिल भारतीय समन्वित तिल व रामतिल (सरगुजा) परियोजना के तहत राज्य में तिल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। परियोजना के तहत विगत 5 वर्षो से खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड रेडुम, डोरमा, कोनकारी, पुत्कलटोली, हेसल व चुरगी गाँव तथा रांची जिले के कांके प्रखंड के सेमलबेरा गांव के 20 जनजातीय किसानों तथा लोहरदगा एवं हजारीबाग जिले के किसानों के खेतों में अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के माध्यम से तिल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खूंटी जिले के रेडुम गांव के प्रगतिशील किसान बिनोद भेंगरा (45 वर्ष) तथा देवलाल भेंगरा बताते हैं कि तोरपा प्रखंड के 20 जनजातीय किसान 5 वर्षों से तिल की खेती कर रहे हैं। इसकी अच्छी कीमत मिल जाती है और ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं होती। इस फसल को मवेशी भी हानि नहीं पहुंचाते हैं। किसान द्वारा इस फसल की देखभाल ठीक से की जाए तो, 1 एकड़ में 2 क्विंटल फसल की पैदावर आसानी से प्राप्त की जा सकती।

परियोजना अन्वेषक डॉ. सोहन राम बताते हैं कि खरीफ मौसम की विषम परिस्थिति में तिल को सबसे उपयुक्त वैकल्पिक फसल कहा जाता है। तिलहन में इस समय प्रदेश के किसान मूंगफली और तिल दोनों की खेती कर सकते हैं। तिल फसल की उपज को कम लागत व कम पानी में करीब 80-85 दिनों की कम अवधि में ली जा सकती है। बीएयू द्वारा विकसित किस्म कांके सफ़ेद, पंजाब में विकसित किस्म टीसी-25 तथा पंतनगर में विकसित शेखर किस्म प्रदेश के लिए उपयुक्त है। इनमें कांके सफ़ेद की उपज क्षमता 6-7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सर्वाधिक 50 प्रतिशत तेल की मात्रा पाई जाती है। इसकी खेती में ऊपरी (टांड़) व पहाड़ी ढलान वाली हल्की रेतीली, बलुई और दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। प्रदेश में जुलाई महीने में तिल की खेती करना फायदेमंद है। इस समय यदि खेतों में जलभराव न हो और खेतों में पर्याप्त नमी मौजूद हो तो किसानों को तुरंत बुवाई का काम निपटा लेना बेहतर होगा। इसकी खेती सहफसली के रूप अरहर, मक्का एवं ज्वार के साथ भी की जा सकती है। इस फसल से पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। डॉ सोहन राम बताते हैं कि अधिक उपज पाने के लिए इसकी बुवाई कतारों में करनी चाहिए, इससे खेत में खरपतवार और दूसरे कामों में आसानी होती है। बोने के समय बीजों का समान रुप से वितरण करने के लिए बीज को रेत (बालू), सूखी मिट्टी या अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ 1:20 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। स्फूर एवं गंधक तत्व की उपलब्धता तिल फसल के उत्पादन एवं दानों में तेल के प्रतिशत को प्रभावित करती है। इसकी पूर्ति के लिए सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक तथा जिंक सल्फेट 10 किग्रा प्रति एकड़ की दर से भूमि में तीन साल में एक बार अवश्य प्रयोग करें। उन्नत प्रभेद एवं वैज्ञानिक तकनीक से तिल की खेती से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है।

पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड के मटियाबांधी पंचायत के बोराशोली गोमरो टोला के किसान सिंचाई स्रोत होने की वजह से गर्मी में भी तिल की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। इस गाँव के किसान पिछले तीन वर्षों से गर्मी में खेत खाली रखने की बजाय तिल की खेती करते हैं। गोमरो के किसान राजू महतो, हिमांशु महतो, ठाकुर दास महतो, चितरंजन महतो बताते है कि दो हजार रुपए प्रति एकड़ लागत और कम मेहनत में तिल उत्पादन से प्रति एकड़ 4 हजार रुपए तक मुनाफा मिल जाता है। 85-90 दिनों में फसल पककर तैयार हो जाती है।

रथिन भद्रा बने झारखंड स्टेट एनवायरनमेंट डेवलपमेंट काउंसिल के को-चेयरमैन

रांची :एसोसिएटद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में रथिन भद्रा को झारखंड स्टेट एनवायरनमेंट डेवलोपमेन्ट कौंसिल के को- चेयरमैन बनाया गया है। रथिन भद्रा जी का *एनवायनमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन* पर काम को देखते हुए और उनका समाज के प्रति अपनी दायित्व को बखूभी निभाने की क्षमता तथा पानी बचाओ और इनोवेटिव जल संचयन योजना भूंगरु के माध्यम से लोगो का सेवा को देखते हुए सम्मानित करने का फैसला एसोचैम ने लिया है । एसोचैम100 साल से भी ज्यादा पुरानी संस्था है। रथिन भद्रा महत्वपूर्ण विषय को बखूबी समाज तक पहुचाने ,लोगों तथा सरकार को जागरूक करने और काम करने के लिये जाने जाते हैं। इसी कड़ी में रथिन भद्रा के नेतृत्व में इस काम को झारखंड में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

युवाओं की क्षमता को सही दिशा देना हमारा कर्तव्य : सीएमडी सीसीएल

सीसीएल में अप्रेंटीसशीप युवाओं के रोजगार विकल्पों को लेकर बैठक

संवाददाता रांची : 07 जुलाई को सीसीएल मुख्यालय, रांची के 'कन्वेंशन सेन्टर'में सीसीएल के सीएमडी, गोपाल सिंह ने सीसीएल में एक वर्ष तक की अप्रेंटीसशीप कर चुके युवाओं से सीधा संवाद किया सीएमडी ने उन्हें संबोधित करते हुये कहा कि एक जिम्मेदार सार्वजनिक उपक्रम के रूप में सीसीएल का कर्तव्य है कि इन युवाओं को अपनी कौशल क्षमता का सर्वोत्कृष्ट उपयोग करने का अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि आप सभी रोजगार के विभिन्न विकल्पों पर भी ध्यान दें। सीसीएल ऐसे प्रशिक्षित युवाओं के लिए मुख्यालय के'रोजगार केन्द्र'के माध्यम से युवाओं को सरकार एवं अन्य संस्थानों में समय-समय पर रोजगार के अवसर संबंधी जानकारी एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करायेगा। चर्चा के दौरान विभिन्न विकल्पों जैसे सीसीएल के वेंडर्स, कॉन्ट्रेक्टर्स एवं अन्य सर्विस प्रोवाईडर के सहयोग से इन प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए, इन युवाओं के क्षेत्रवार विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के सुझाव पर, राज्य सरकार के सहयोग से विभिन्न प्रशिक्षण जैसे एचएमवीड्राईविंग लाईसेंसआदि, स्वरोजगार एवं व्यापार करने के लिए बैंकों से आसान किस्तों पर लोन, भारत सरकार की एनएसडीसी एवं अन्य योजनाओं द्वारा उपलब्ध रोजगार के अवसर पर संवादकिया गया साथ ही किस प्रकार से सीसीएल इस दिशा में इन युवाओं को सहयोग कर सकता है इस पर भी परिचर्चा की गयी।

बैठक में सीसीएल के निदेशक तकनीकी वी.के. श्रीवास्तव, महाप्रबंधक ,एस.के. सिंह, महाप्रबंधक,राजीव सिंह, आर.पी. सिंह,महाप्रबंधक ,वी.के. सिंह, महाप्रबंधक, एजाज अहमद, महाप्रबंधक , उमेश सिंह, महाप्रबंधक सुश्री रश्मि दयाल, मुख्य प्रबंधक (सीएसआर)के.एल. सुन्दर एवं एसबीआई, सीसीएल कैम्पस से प्रबंधक, श्रीमती मिनल सुमैयासहित अन्य उपस्थित थे।

महज एक नदी नहीं बल्कि मां स्वरूपा है गंगा....

डॉ.कृष्ण कुमार मिश्र

आपने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में पीएच-डी. की उपाधि प्राप्त की। आप टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई के होमी भाभा विज्ञान केन्द्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लोकप्रिय विज्ञान लेखक के रूप में आपकी अपार ख्याति है जोकि हिन्दी में आपके व्यापक लेखन से निर्मित हुई है। आपके 250 से अधिक लेख तथा 22 पुस्तकें प्रकाशित हैं। राजभाषा गौरव पुरस्कार, होमी जहाँगीर भाभा स्वर्ण पुरस्कार, शताब्दी सम्मान, राजभाषा भूषण पुरस्कार, इस्वा सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित डॉ.मिश्र मुंबई में निवास करते हैं।

वास्तव में गंगा भारतीय संस्कृति का ऐसा महाप्रवाह है जो लोक और शास्त्र दोनों में समान रूप से सदियों से सतत प्रवाहमान है। यह प्रवाह हजारों वर्षों से भारतीय भूखंड के लोक को निरन्तर संपोषित तथा अनुप्राणित करता रहा है। लोकजीवन में गंगा पवित्रता, निर्मलता, नैरन्तर्य तथा मोक्षदायी अमृत का प्रतीक है। नदियां किस तरह से हमारे लोकजीवन, लोकचिंतन तथा लोक परंपरा और के केन्द्र में रही हैं, इसके साक्ष्य हमारे शास्त्रों में मिलते हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख करना समीचीन होगा। श्रीमद्भगवद्गीता में दशम अध्याय के 31 वें श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को नदियों में गंगा बताया है

यथा- स्रोतसामस्मि जाह्नवी।

दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के नदी सूक्त में गंगा का उल्लेख सर्वप्रथम है। गंगा, यमुना के साथ पौराणिक सरस्वती नदी का साहचर्य भी इस ऋचा में द्रष्टव्य है..

इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या ।
असिकन्या मरुद्वृधे वितस्तयार्जीकीये शृणुह्या सुषोमया ।।

ऋग्वेद 10.75.5

संस्कृत के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि रचित गंगा -स्तुति मननीय है।

ब्रह्माण्ड खण्डयन्ती हरशिरसिजटावल्लिमुल्लासयन्ती
स्वर्लच्चकादापतन्ती कनकगिरिगुहागण्डशैलात्स्खलन्ती।
क्षच्णीपृष्ठे लुठन्ति दुरितचयचमू निर्भरं भर्त्सयन्ती
पाथर्चधिं पूरयन्ती सुरनगर सरित् पावनी नः पुनातु।।

उत्तराखंड के देवप्रयाग में भगीरथी तथा अलकनंदा नदियों के संगम में गंगा नदी का निर्माण होता है। भगीरथी नदी गोमुख नामक ग्लेशियर से निकलती है जो कि गंगोत्री से 18 किमी दूर ऊंचाई पर हिमालय में स्थित है। अलकनंदा हिंदूओं के पवित्र तीर्थ तथा चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से होकर गुजरती है। प्रयागराज में यमुना नदी गंगा में मिलती है। इस स्थान को संगम के नाम से जाना जाता है।माना जाता है कि प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा आदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसलिये यहां के संगम को त्रिवेणी संगम भी कहते हैं तथा प्रयागराज को संगमनगरी भी कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेले के नाम से प्रयागराज में लगता है। हजारो वर्षों से लग रहे इस अद्वितीय मेले को देख कर यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत का दर्जा दिया है।

ब्रह्माण्ड को तोड़कर आती हुई, देवाधिदेव महादेव के जटाजूट के सुशोभित करती हुई, स्वर्गलोक से गिरती हुई, सुमेरु पर्वत को समीप पाषाणों से टकराती हुई, पृथ्वी पर बहती हुई, पापो की प्रबल सेना को त्रास देती हुई, समुद्र को पूर्ण करती हुई यह दिव्य गंगा नदी हम सबको पवित्र करे। स्कन्द पुराण के काशी खण्ड, अध्याय 29 में गंगा कव अकारादि क्रम में एक हजार नाम (गंगा सहस्रनाम) दिए गए हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो गंगा का दर्शन कर लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जो गंगा को स्पर्श कर लेता है वह मृत्युपरान्त स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है, किन्तु जो गंगा में स्नान भी कर लेता है वह परम पुरुषार्थ मोक्ष का भागी बन जाता है। यथा-

दृष्वारेत हरेत पापं स्पृष्वा तु त्रिदिवं नयेत।
प्रसङ्गेनापि या गंगा मोक्षदा त्ववगाहिता।

वैष्णवों ने गंगा को गीता एवं गायत्री के समान पवित्र तथा पूजनीय माना है तथा स्तोत्रों में उसी रूप में उसका गुणगान किया है। इनका नित्य पांच बार स्मरण कर लेने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तथा-

गंगा गीता च गायत्री गोविन्दे गरुडध्वजः।
पंचैतान्स्मरतो नित्यं सर्वपाप प्रणश्यति।।

संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास की गंगाष्टक रचना सुप्रसिद्ध है। इसके श्लोक में शब्दों तथा ध्वनियों की महक लयात्मकता अद्भूत है।

नमस्तेऽस्तु गंगे त्वदंगप्रसंगाद्
भुजंगास्तुरंगा कुरंगाः प्रवंगाः।
अनंगारिरंगाः ससंगाः शिवांगाः
भुजंगाधिपांगीकृतांगा भवन्ति।।

तुलसीदास ने रामचरित मानस के बालकांड में गंगा की महत्ता का वर्णन चौपाई में कुछ इस तरह किया है-

कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहँ हित होई।।

5 कीर्ति, यश तथा सम्पत्ति लच्क मंगलकारी हो जैसे कि माँ गंगा सर्वकल्याण-कारिणी हैं।

इलेक्ट्रोनिकी आपके लिये से साभार

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

संपादकीय

पारंपरिक भोजन ही उत्तम

देश में अभी धान रोपाई का मौसम है। अलग -अलग प्रदेशों में इस भीगे हुये मौसम में कीचड़ पानी सने खेतों से जब कृषक और मजदूर धान रोप कर घर आते हैं तो इस मौसम का कोइ न कोई खास व्यजंन बनता है। ये व्यजंन इस मौसम की पारंपरिक पहचान होते हैं। इसे वैज्ञानिक नजरिये से देखेंगे तो इसके पीछे का विज्ञान भी नजर आयेगा। इन व्यंजनों की सामग्री मॉनसून के अनुसार होती हैं जो पानी भरे खेतों में काम करने वाले बैलों से लेकर खेतिहरों और मजदूरों को राहत पहुंचाते हैं साथ ही मौसमी दुष्प्रभाव से बचाते भी हैं। अगर दक्षिण भारत के समुद्रतटीय राज्यों में भोजन में इमली डालने का प्रचलन रहा है तो उसका मूल कारण वहां के जल में उपलब्ध खारेपन को कम करने के लिये है। यानि हमारा पारंपरिक आहार व्यवहार पूरी तरह से वैज्ञानिक रहा है।

लंबे समय तक यह भ्रम फैलाया गया कि भारतीय भोजन पूरी तरह से पौष्टिक नहीं हैं और इन्हें ग्रहण करने के बाद देर तक आराम की जरूरत पड़ती है और यह आलस्य बढाता है? आज समृद्धी के साथ ही हम भारतीयों ने पश्चिमी तौर तरीकों के भोजन को अपनाया और इसी का हश्र है कि मोटापे के साथ ही आम शहरी कई रोगों से परेशान है।

आधुनिक दिखने की दौड़ में चाइनीज यूरोपीय और इतावली भोजन का भारतीय तौर तरीका हमारे मुंह का जायका तो बना रहा है, पर देश का स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है। इसका एक कारण इन विदेशी व्यंजनों को खतरनाक मिलावटी चीजों से भारतीय तरीकों से तैयार करना भी है। वहीं गौर से देखें तो हमारा पारंपरिक भोजन मौसम, क्षेत्र और स्वास्थ्य के लिहाज से जांचा परखा हुआ है जिसे हम आज उपेक्षित कर रहे हैं?

आज भारतीयों में पेट का रोग आम है साथ ही मोटापाजनित रोगों से भी लोग त्रस्त हैं। इसका मूल कारण जंक फूड हैं लंबे समय से बताया जा रहा है कि ये जंक फूड युवाओं किशोरों का स्वास्थ्य बर्बाद कर रहा है। फास्ट फूड के दूकानों और होटलों में बोतलों में टमाटर सॉस के नाम पर दिखने वाले लाल सॉस में एक छंटाक भी टमाटर नहीं होते एक जानकार का कहना है कि झारखंड में बंगाल से आने वाले कोहड़े से यहां नकली टमाटर सॉस बनाया जाता है। हकीकत है कि हमारा देसी और पारंपरिक भोजन पौष्टिक और स्वास्थकर भी है। आज से दो दशक पहले जब पिज्जा, बर्गर, हॉटडॉग बेचने वाली अमेरिकी कंपनियों ने भारतीय हाइवे में अपने काउंटर खोले तो उनकी बिक्री न के बराबर थी? उन्होंने जानकारी जुटायी तो इसका कारण हाइवे में स्थित भारतीय भोजनों वाले ढाबे थे। तब इन विदेशी कंपनियों ने यह प्रोपगंडा किया कि भारतीय ढाबों के बने भोजन स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हैं । जबकि आज कोरोना से बचाव में हमारा पारंपरिक रोग प्रतिरोधक भोजन ही बहुत कारगर रहा है।

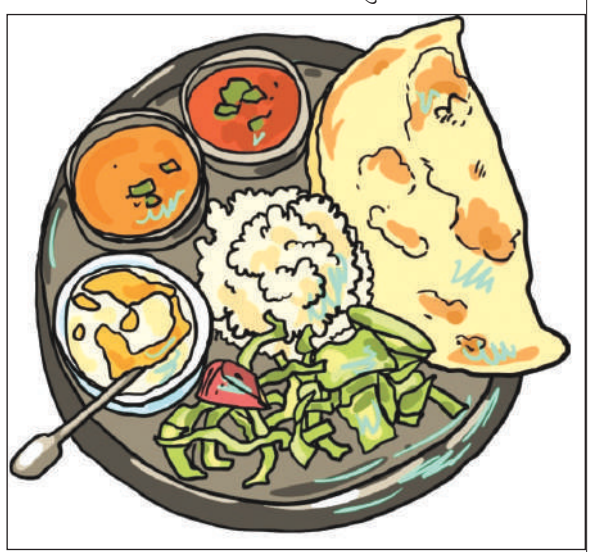

रेलवे और मारूति की रिकार्ड जुगलबंदी

कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजूकी (एमएसआईएल) ने इस साल भारतीय रेलवे के जरिये 1,78,000 कारों की आपूर्ति की जो कंपनी की कुल बिक्री का करीब 12 फीसदी है। रेलवे के जरिये मारुति की कारों की ढुलाई में पिछले साल के मुकाबले इस साल 15 फीसदी का इजाफा हुआ है।

गुडगांव की कार कंपनी ने पिछले छह साल के दौरान 6,70,000 लाख कारों को भारतीय रेल के जरिये गंतव्य तक भेजा। इस प्रकार इसमें 18 फीसदी सीएजीआर की वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी के मुताबिक उसने रेलवे के जरिये पहली बार मार्च 2014 में कारें भेजी थी। रेलवे के जरिये नई कारों को उनके आपूर्ति स्थल तक भेजने से कंपनी ने करीब 3,000 टन कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही 10 करोड़ लीटर ईंधन की भी बचत हुई है। इससे कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले एक लाख ट्रक के चक्कर बचाए हैं।

मारुति सुजूकी के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ केनिची आयुकावा ने कारों को भेजने के लिए रेलवे का इस्तेमाल करने के बारे में कहा, कारें भेजने की बढ़ती संख्या को देखते हुए हमारी टीम ने बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक की जरूरत महसूस की। हमने महसूस किया कि न केवल विस्तार के लिए बल्कि जोखिम कम करने के लिए भी हमें सड़क माध्यम के अलावा दूसरे माध्यमों को देखना चाहिए। शुरुआत में 125 कारों को ले जाने की क्षमता वाले रेलवे वैगन का इस्तेमाल किया। उसके बाद डबल-डेकर रैक का इस्तेमाल शुरू हुआ जिसमें 265 कार ले जाने की क्षमता होती है। इन रैकों के जरिये अब तक 1.4 लाख कारें भेजी जा चुकीं हैं। अब कंपनी 27 रैक का इस्तेमाल कर रही है। इनमें प्रत्येक रैक में 318 कारें भेजी जा सकतीं हैं।

मारुति ने कहा है कि वह देश की पहली कार निर्माता कंपनी है जिसके पास ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (एएफटीओ) लाइसेंस है। वर्तमान में कंपनी पांच टर्मिनल- गुरुग्राम, फारुखनगर, कठुवास, पाटली, डेट्रोज- से कारों का लदान करती है।

यूरोप, चीन, अमेरिका और जापान में भी फैल सकता है जीका वायरस

जलवायु में आ रहे बदलावों और बढ़ते तापमान के चलते जीका वायरस उन ठन्डे क्षेत्रों में भी फैल सकता है जहां पहले इसके फैलने की सम्भावना कम थी शोधकर्ताओं के अनुसार 2080 तक तापमान में आ रहे बदलावों के चलते यह वायरस दक्षिण और पूर्वी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, जापान के दक्षिणी हिस्सों और उत्तरी चीन तक फैल सकता है यह शोध यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया है, जोकि अंतराष्ट्रीय जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द रॉयल सोसाइटी में प्रकाशित हुआ है। इस शोध के लिए शोधकर्ताओं ने आईपीसीसी के जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मॉडलिंग से प्राप्त सबसे गंभीर परिणामों को लिया है । गौरतलब है कि मच्छरों की यह दो प्रजातियां उन क्षेत्रों में जहां तापमान ज्यादा होता है, इस वायरस को फैला सकती हैं।

आपदा को अवसर बनाया जा रहा है या दिया जा रहा है?

क्लाइमेट कहानी

कोई तो वजह होगी जो ऊपरवाले ने कोयले को हमारी नजरों और पहुँच से दूर, धरती की गहराईयों में दबा कर रखा है। शायद इसलिए क्योंकि कोयला हमारे लिए ज़रूरी नहीं। क्योंकि ज़रूरी होता, तो ऊपरवाला हमसे इतनी जद्दोजेहद नहीं कराता। कोयला भी फिर हमें हवा और पानी की तरह ही मुहैय्या करा दिया जाता। दरअसल, कोयला हमारी ज़रूरत नहीं, चाहत है। ज़रूरत तो बस ऊर्जा है। इसे ऐसे समझिये, कि हमारी ज़रूरत बस दो वक़्त का खाना है, लेकिन हमारी चाहत है बढ़िया रेस्टोरेंट में ज़ायकेदार खाना। अब यहां सोचने बैठो तो एहसास होता है कि इस ज़िन्दगी को चाहतों ने ही तो बर्बाद कर रखा है। ज़रूरतें तो बड़ी कम और मासूम हैं।

खैर, बात कोयले की करें तो माजरा असल में ये है कि हमें इसकी ऐसी आदत पड़ गयी है, या यूं कहें कि हमें हमारी सरकारों ने इसकी ऐसी आदत डलवा दी है, कि हमें अब ये चाहत अपनी ज़रूरत लगने लगी है।मित्रों, आप ज़रा दिल पर हाथ रख कर बताइए। क्या आपको काला कोयला पसन्द है? उसको उठाने के बाद हाथ धोने का फ़ौरन ख्याल आता है कि नहीं? कपड़ों पर उसके दाग़ लग जाने का डर सताता है कि नहीं? भाइयों और बहनों, असल बात तो ये है, कि कोयला किसी को पसन्द नहीं। पर्यावरण को तो कतई पसन्द नहीं। हरे पत्ते पर राख़ की परत भला कोई पसन्द कर सकता है? लेकिन हमारी सरकार को शायद कोयले की कालिख़ और राख़ बड़ी पसन्द है।अब ये ना सोचें तो भला क्या सोचें? आप ही बताइए, इसे विडम्बना नहीं तो और क्या कहेंगे कि एक तरफ़ तो सरकार, जलवायु परिवर्तन का भारतीय उपमहाद्वीप पर होने वाले असर की एक ज़बरदस्त शोध रिपोर्ट जारी कर, देश को हिदायत देती है कि अगर हमने पर्यावरण के हित में सही फ़ैसले नहीं लिए तो सदी के अंत तक हमारी धरती का तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जायेगा; और दूसरी ओर वही सरकार उस रिपोर्ट के जारी होने के अगले ही दिन कोयले के वाणिज्यिक उपयोग के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत कर देती है।सरकार अपने पक्ष में दलील देते हुए कहती है कि नीलामी की यह घोषणा ऐतिहासिक है और देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक कदम है। पीआईबी की विज्ञप्ति पर नज़र डालें तो पता चलता है कि यह नीलामी इसलिए ऐतिहासिक कही जा रही है क्योंकि इसके माध्यम से 'देश का कोयला क्षेत्र बाधाओं की बेड़ियों से मुक्त होगा और प्रगति के नए अध्याय रचेगा'। विज्ञप्ति में नीलामी को आत्मनिर्भरता से जोड़ते हुए कहा गया है कि 'जब से स्वनदर्शी और निर्णायक छवि के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' का उद्घोष किया है तब से देश के कोयला क्षेत्र ने भी संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से बड़े अभियान के लिए अपनी कमर कस ली है।आगे, इस नीलामी प्रक्रिया को आत्मनिर्भर भारत की ओर देश का एक मज़बूत कदम सिद्ध करते हुए विज्ञप्ति में लिखा गया है कि 'कोयला खदानों की इस नीलामी प्रक्रिया से देश में ऊर्जा सुरक्षा की मजबूत नींव रखी जाएगी। अतिरिक्त कोयला उत्पादन से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे और कोयला क्षेत्र में व्यापक निवेश होगा। इन प्रयासों से 1 बिलियन टन का कोयला उत्पादन होगा जिससे 2023-24 में अनुमानित घरेलू थर्मल कोल की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा।'अब यहां एक सवाल मन में कौंधता है कि अपने देश की प्राकृतिक संपदा और धरोहर को बेच कर कोई देश कैसे आत्मनिर्भर बन सकता है? अब तक तो इन खदानों पर हक़ देश की ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां थीं। लेकिन अब तो ये सबके लिए खोल दी गयी हैं। इस सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी देने से किसका राजस्व बढ़ेगा? और विदेशी निवेश से भारत की आत्म-निर्भरता के लक्ष्य कैसे पूरे हो रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते पीआईबी की इस विज्ञप्ति में।

कोयला खादानों और रोज़गार की बात हो तो ज़हन में नाम आता है छतीसगढ़ के कोरबा ज़िले का जिसका लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा कोयला खनन के काम आता है। इसी वजह से कोरबा को कोयले का हब भी कहते हैं और साथ ही उसे बिजली उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। छतीसगढ़ एक जनजातीय प्रधान राज्य है। अब अगर इतने सालों में कोयला खनन से वहां के मूल जनजातीय निवासियों को फ़ायदा मिलता तो अब तक तो वहां सबके वारे न्यारे हो जाने चाहिए थे। बिल्कुल वैसे, जैसे गुड़गांव और नोयडा के किसानों के हुए जमीन बेच कर। लेकिन वहां हुआ तो दरअसल उसका पूरा उलट। डाउन टू अर्थ मैगज़ीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक़, ''कोरबा के ज़िला रोजगार कार्यालय के अनुसार वर्ष 2017 में कोयला खदानों मे कार्यरत श्रमिकों की संख्या लगभग 14 हजार थी, जबकि इसी दौरान पंजीकृत बेरोज़गारों की संख्या इससे कई गुनी अधिक थी। यह आंकड़े बताते हैं कि खदानों के खुलने का अर्थ, स्थानीय लोगों के लिए न तो बढ़े हुये रोजगार के अवसर हैं और न ही यह ग़रीबी से मुक्ति का मार्ग है। आज कोरबा जिले के लगभग 40 फ़ीसदी लोग ग़रीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जिनमें से बहुसंख्यक आदिवासी ही हैं। कुल मिलाकर, तथाकथित, देशहित में कोरबा के बहुसंख्यक आदिवासी समाज ने न सिर्फ़ खोया अपना जल, जंगल, और ज़मीन, बल्कि उस के एवज़ अगर कुछ पाया तो वो है आभाव, उपेक्षा, और अन्याय। कोयला खदानों और उनसे जुड़ी ऐसी विसंगतियों की कहानी लम्बी है। वो कहानी फिर कभी। फ़िलहाल विचारों को जलवायु परिवर्तन के बीच कोयला खादानों की इस नीलामी के तर्क समझने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं।

ये तो आप भी समझते हैं कि कोयला विशुद्ध रूप से कार्बन है और उसके जलने से हमारे पर्यावरण को होने वाले नुकसानों के बारे में हमें स्कूल से पढ़ाया जा रहा है। तो अब ज़रा सोचिये कि इस फ़ैसले से आख़िर पर्यावरण को क्या फ़ायदा हो सकता है। यह सोचना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जहाँ एक ओर इस नीलामी का उद्देश्य कोयला क्षेत्र को व्यावसायिक व वाणिज्यिक उपयोग के लिए खोल कर निर्यात बढ़ाना है, वहीं दूसरी ओर तमाम आंकड़ें बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर कोयले की मांग बढ़ने की जगह घट रही है। जर्मनी ने तो कोयले से हटते हुए अपनी राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति तक घोषित कर दी है। कोयले का यह मोह समझ से और भी परे हो जाता है जब याद आता है कि भारत ने तो दुनिया के और देशों की तरह कोयले से पीछे हटते हुए गैस आधारित अर्थव्यवस्था और रिन्युबल एनेर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए 2022 तक उत्पादन को 1.75 लाख मेगावाट तक ले जाने और फिर 2030 तक इसे 4.5 लाख मेगावाट तक ले जाने का टारगेट रखा है। एक पल को सरकारी नज़रिए से भी देखें तो भी यही समझ आता है कि केंद्र और राज्य सरकारें इस फ़ैसले पर एक मत नहीं हैं। जहाँ झारखण्ड सरकार नीलामी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी, वहीँ छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को इस फ़ैसले में संशोधन करने की चिट्ठी लिख डाली है। कसम से बड़ी मुसीबत है। कुछ समझ नहीं आ रहा। दिमाग़ घूम गया लेकिन दिल तक को तसल्ली नहीं दे पा रहे कि आख़िर कैसे कोयला हमारे देश और हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। आख़िर कोयले की खोदाई तो एक लिहाज़ से ऐसी है कि आप किसी की कब्र खोद उसकी लाश निकालें और कहें कि कहां छिपे हो, चलो बाहर आओ। बहुत हुआ आराम। अब करो कुछ काम। तो जनाब अब लाश से काम कर-एँगे तो मंज़र तो खौफ़नाक ही होगा। क्या पता आने वाले वक़्त में कोयला बिजली घरों से निकलते धुंए के गुबार के पीछे हमारे-आपके भूत गुनगुनाते हुए सुनायी दें, ''हम'पे ये किसने...काला रंग डाला....चाहत ने हमारी हमें...मार डाला...अल्लाह...मार डाला...''ओह, अब समझ आया इस नीलामी की शक्ल में हो क्या रहा है। बात दरअसल कोविड की इस आपदा को अवसर बनाने की हो रही थी। लेकिन अफ़राह-तफ़रीह में किसी ने शायद गलत सुन लिया। और अब तमाम सबूतों और गवाहों के बयानों के मद्देनज़र यह समझ आ रहा है कि आपदा को अवसर बनाया नहीं आपदा को अवसर दिया जा रहा है।

- विश्व के 5 बड़े कोयला खनिकों में से 4 ने कोयले से दूरी बनाने के अपनी योजना की घोषणा की है
- ग्यारह ट्रिलियन डॉलर से अधिक की पूँजी का प्रबंधन करने वाले लगभग 1,110 संस्थानों ने जीवाश्म ईंधन से व्यापारिक दूरी की प्रतिबद्धता ज़ाहिर की है
- भारत की इस्पात माँग का 14% से 17% .के बीच सिकुड़ जाने की सम्भावना है. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण गतिविधियों में आयी मंदी और साथ में सरकार के घटते सार्वजनिक व्यय के चलती स्थिति में सुधार जल्दी होता नहीं दिखता

क्लीन एयर फण्ड के एक सर्वे के मुताबिक 95% स्वास्थ्यकर्मी चाहते हैं की प्रधान मंत्री मोदी कोयले की जगह अक्षय ऊर्जा को प्राथमिकता दें।

मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ा रहा है केंचुआ खाद

दिव्यांश सिंह

पांच दिन में खराब होनी वाली सब्जी अब दस दिन चल रही

आज के समय में किसान अधिकतर रासायनिक खाद से खेती कर रहे हैं। रासायनिक खाद फसल को स्वादहीन करने, फसल में पोषक तत्वों की कमी करने, मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम करने के साथ ही आपको गंभीर रोगों से घेरने का भी काम करती है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कुछ वर्षों पहले किसानों को केंचुआ खाद के महत्व को बताया और उसको बनाने का प्रशिक्षण दिया। एक माह चली ट्रेनिंग के बाद बिल्हौर तहसील के 20 किसान केंचुआ खाद से खेती करने को तैयार हुए। यह किसान पिछले तीन साल से केंचुआ खाद से खेती कर रहे हैं, अब इनका कहना है, जो फसल हमको खराब होने के डर से जल्दी बेचनी पड़ती थी। उसकी क्षमता में विकास हुआ है, वह चार से पांच और दिन स्वस्थ रहती है। साथ ही रासायनिक खादों से खेत की मिट्टी में उर्वरक क्षमता की कमी आई थी। उस कमी को केंचुआ खाद ने दूर कर दिया जो अब नहीं है। सीएसए की जैविक खेती के प्रचार एवं प्रसार परियोजना के प्रभारी डॉ डीपी सिंह ने बताया रासायनिक खाद मिट्टी में जीवांश कार्बन को कम कर देती हैं।

रासायनिक खाद के अंधाधुंध उपयोग की वजह से बिल्हौर तहसील के खेतों की मिट्टी में जीवांश कार्बन 0.2 से 0.4 प्रतिशत है। जबकि स्वस्थ मिट्टी में जीवांश कार्बन न्यूनतम 0.8 प्रतिशत होना चाहिए । मिट्टी को पौधे का विकास करने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, आयरन, जस्ता और मैग्नीज समेत 17 तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जो कि केंचुआ खाद से पूरे हो जाते हैं।

अगर आप रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो आपको प्रत्येक पोषक तत्व के लिए अलग-अलग खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। किसानों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ उनको केंचुआ खाद बनाने के उपकरण निशुल्क सीएसए द्वारा मुहैया करवाए गए हैं। समय-समय पर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक उन किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।

अकबरपुर सिंह गांव के किसान कौशल किशोर तिवारी ने बताया पिछले तीन साल से केंचुआ खाद से खेती कर रहे हैं। सीएसए ने हम लोगों को केंचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया और उपकरण निशुल्क मुहैया करवाए थे। इसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ी है।

हम सब्जियों की खेती करते हैं । पहले हमारा टमाटर और भिंडी 4 से 5 दिन के भीतर खराब हो जाता था जिस वजह से हमको जल्दी बेंचना पड़ता था। अब वही सब्जियां 10 दिन तक रखने पर खराब नहीं होती हैं। केंचुआ खाद घर में बन जाती है। जबकि रासायनिक खाद बाजार से खरीदकर लानी पड़ती थी, उसका पैसा बच जाता है। किसान विजय सिंह ने बताया उनके 30 बीघा खेती है, जिसमें वह सब्जियां बोते हैं। सीएसए से प्रशिक्षण मिलने के बाद वह केंचुआ खाद से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। इस-ाका उपयोग करने से हमारी सब्जियां 4 से 5 दिन ज्यादा रखने पर भी खराब नहीं होती है। सब्जियों को बनाकर खाने में स्वाद अच्छा होता है।सबसे बड़ी बात रासायनिक खादों को लाने में हमारा रुपया लगता था, इसको हम घर पर ही बना लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान बताया गया था रासायनिक खादों से उपजी फसल से कैंसर समेत कई गंभीर रोग होते हैं । इस वजह से हमने खासकर जैविक खादों से खेती करना शुरू कर दी। सीएसए के वैज्ञानिक हमारा समय समय पर आकर मार्गदर्शन करते रहते हैं। जैविक खादों से खेती करने पर मिट्टी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है साथ ही खेती में पानी भी कम लगता है। 2017 में विश्व विद्यालय की एक परियोजना शुरू हुई थी, जिसके परिणाम बेहतर मिले हैं। बिल्हौर तहसील के गांव में परियोजना शुरू होने से पहले मिट्टी में जीवांश कार्बन 0.4 प्रतिशत था, जो कि अब केंचुआ खाद का प्रयोग होने से 0.48 प्रतिशत हो गया है। हम आगे भी जैविक खेती को लेकर कई परियोजनाएं चलाने और किसानों को प्रशिक्षण देने की योजना बना रहे हैं।

एन-95 मास्क को कीटाणु रहित कर देगा यह डिवाइस

आईआईटी दिल्ली-इनक्यूबेटेड स्टार्टअप 'चक्र इनोवेशन' ने ऐसा डिवाइस बनाया है, जो एन-95 मास्क को दस बार इस्तेमाल करने लायक बना देगा। कोरोनोवायरस के खिलाफ लड़ने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एन 95 मास्क पर उच्च निर्भरता का एहसास करते हुए आईएएन - फंड समर्थित आईआईटी दिल्ली-इनक्यूबेटेड क्लीनटेक स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने चक्र डिकोव यानी एक ओजोन-बेस्ड डिकंटेमिनेटिंग (कीटाणुरहित) डिवाइस विकसित किया है। ताकि एन95 मास्क को सुरक्षा के साथ दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जा सके।

यह इनोवेशन यानी चक्र डिकोव एक ऐसे समय में लॉन्च किया गया है, जब देश को महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। एन 95 मास्क का असुरक्षित पुनः इस्तेमाल स्वास्थ्य पेशेवरों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। इसके अलावा, बायोमेडिकल कचरे में वृद्धि अतिरिक्त संक्रमण और पर्यावरणीय जोखिम का कारण बन सकती है। इन समस्याओं को हल करने के लिए आईआईटी दिल्ली-इनक्यूबेटेड स्टार्टअप ने चक्र डिकोव के रूप में सस्ती तकनीक ईजाद की है जो सिर्फ 90 मिनटों में एन 95 मास्क को सुरक्षित व पुनः इस्तेमाल करने योग्य बनाने में मदद करता है।

क्या मगरमच्छ कभी दो पैरों पर चलते थे?

आपने भी क्या दो पैरों पर चलने वाले मगरमच्छ की कहानी सुनी है. अब तक यह कल्पना से परे था लेकिन वैज्ञानिकों की टीम के पुरातात्विक खोजों से इस बात की जानकारी सामने आ रही है. क्या सचमुच ऐसा कभी हुआ होगा?

प्राचीन मगरमच्छों के बारे में लंबे समय से यही माना जाता है कि वो अपने आधुनिक वंशजों की तरह ही चार पांवों पर चलते थे. एक नई स्टडी में उनके दो पैरों पर चलने की संभावना जताई गई है. चीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के रिसर्चर दक्षिण कोरिया के जींजू फॉर्मेशन में पैरों के कुछ निशान ढूढने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं. यह रिसर्च रिपोर्ट नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट में छपी है. दक्षिण कोरिया का यह इलाका पुरातत्व के लिहाज से बेहद अमीर है. यहां पर छिपकिली, मकड़े और शिकारी पक्षी रैप्टर की कुछ प्रजातियों के 12 करोड़ साल पुराने अवशेष मिले हैं. रिसर्चरों का मानना है कि जिन मगरमच्छों के कदमों के निशान मिले हैं वो कम से कम तीन मीटर लंबे थे उनका वैज्ञानिक नाम बात्राचोपस ग्रांडिस है. यह मगरमच्छ तनी हुई रस्सी पर चलने वाले बाजीगरों की तरह दो पैरों पर चलता था. चिंजू नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के क्युंग सू किम का कहना है, वो डायनोसॉर जैसे ही चलते थे, लेकिन पैरों के ये निशान डायनोसॉर के नहीं हैं।

दो पैरों पर चलने वाले मगरमच्छ के कदमों के निशान

पहले रिसर्चरों को लगा था कि ये निशान टेरोसॉर के हैं. यह डायनोसॉर की ही एक प्रजाति है लेकिन उसके पंख होते थे. यह डायनोसॉर 6.6 करोड़ साल पहले तक धरती पर मौजूद था. हालांकि अब इन्हें क्रोकोडाइलोमॉर्फ फैमिली का एक सदस्य माना जा रहा है जिसकी अब तक खोज नहीं हुई थी. करीब 10 इंच लंबे पैरों के निशान से मगरमच्छ के इस रिश्तेदार के आकार का आकलन किया गया है.

क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के जीवाश्म विज्ञानी एंथनी रोमिलियो भी इस रिसर्च रिपोर्ट के लेखकों में शामिल हैं. रोमिलियो का कहना है कि पैरों के निशान किसी वयस्क इंसान के जितने ही लंबे हैं. हालांकि इनके शरीर की "लंबाई तीन मीटर से ज्यादा तक की रही होगी." इसका मतलब है कि वह अपने समकालीन रिश्तेदारों की तुलना में करीब दोगुना लंबा था. यह प्राचीन मगरमच्छ मुमकिन है कि दो पैरों पर चलता रहा होगा और इंसानों की तरह ही अपनी एड़ी घसीटता होगा. यही वजह है कि इसके पैरों के निशान काफी गहरे हैं.

इन मगरमच्छों का जब प्रयोगशाला में मॉडल बनाने की कोशिश की गई तो पता चला कि इनका गुरुत्व केंद्र बहुत कम था. रोमिलियो ने बताया कि खुदाई वाली जगह पर ना तो हाथों के निशान मिले ना ही पूंछ के. इसके साथ ही इसके चलने का मार्ग भी पतला है. इन सब कारणों से इस संभावना को मजबूती मिलती है कि यह दो पैरों पर चलता रहा होगा. इस खोज से क्रिटेशस काल के दूसरे जीवों के बार में भी नई जानकारियां सामने आएंगी. टेरोसॉर उसी दौर का जीव है. वैज्ञानिकों ने ध्यान दिलाया है कि इस नई खोज के बाद जीवाश्म मिलने की कुछ दूसरी जगहों पर भी मिले जीवाश्मों का भी नए सिरे से अध्ययन किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन से 'मारमोट' का जीवन खतरे में

मारमोट एक प्रकार की बड़ी गिलहरी की प्रजाति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय, लद्दाख और देअ-ोसाई पठार आदि में पाई जाती है। जलवायु परिवर्तन ने अन्य जीवों की तरह इनके जीने के लिए भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। लंबे समय तक होने वाली कठोर सर्दियां जब भोजन की कमी होती है, इस समय जानवर काफी हद तक ऊर्जा के लिए वसा के भंडार पर निर्भर करते हैं। सर्दियों में अधिकतर जानवर सीतनिद्रा या पलायन करने लगते हैं।

प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित इस नए अध्ययन में कहा गया है कि गर्मियों और सर्दियों के मौसम में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से मारमोट का जीवन अलग तरह से प्रभावित होता है।अबतक किए गए शोध ने 40 साल के जीवन-इतिहास के आंकड़ों का विश्लेषण किया। विश्लेषण यह जानने के लिए किया गया कि कैसे पीले-बेल वाले मारमोट ने गर्मियों के मौसम की लंबी अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन से किस तरह मुकाबला किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निरंतर जलवायु परिवर्तन गर्मियों के पैटर्न को बदल सकता है, क्योंकि अधिक गर्मी से पौधों के जीवित रहने पर असर पड़ेगा। इस तरह का वातावरण मारमोट आबादी को भी प्रभावित करेगा, उन्हें खाने का चारा नहीं मिलेगा और वे गर्म और शुष्क आवासों में नहीं रह पाएंगे।

सीआरपीएफ अधिकारियों ने लिया प्रशिक्षण

रांची :रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता एस उरांव के मार्गदर्शन में सम्पन्न, एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में सीआरपीएफ के लगभग 20 अधिकारियों ने प्रशिक्षण लिया । इसमें उन्होंने दूरसंचार विभाग किस तरह काम करता है एवं किस किस उपकरण तथा तकनीक का इस्तेमाल होता है यह सीखा। यह सीआरपीएफ और रेलवे के बीच बेहतर समन्वय की ओर एक कदम है। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में वरिष्ठ मंडल सिगनल एवं दूरसंचार विभाग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक इन्टरलॉकिंग सिस्टम बिल्डिंग आदि का भी दौरा किया और वहां भी किस तरह काम होता है उसे जाना। इस पूरे प्रशिक्षण में ए के श्रीवास्तव सीनियर सेक्शन अभियंता ने इन अधिकारीयों को प्रशिक्षण दिया। इनके साथ श्रीमती सलमा लकड़ा सीनियर सेक्शन अभियंता भी उपस्थित थीं।

रांची रेल मंडल का झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक

रांची :रेल मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जोनल तथा मंडल स्तर पर ''बिज़नेस डेवलपमेंट यूनिट'' का गठन किया जाये, इसी के अंतर्गत राँची रेल मंडल पर ''बिज़नेस डेवलपमेंट यूनिट''का गठन किया गया । वर्तमान परिस्तिथि में माल ढुलाई कि क्षमता में वृद्धि करना , पारम्परिक लदान के अलावा अन्य भावी लदान कों अधिक से अधिक आकृष्ट करने हेतु प्रयास करने का कार्य यूनिट द्वारा किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत आज दिनांक 8 जुलाई 2020 को अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित के नेतृत्व में यूनिट के समन्वयक एवं सदस्यों की झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों के साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के सीताराम रुंगटा सभा गृह में बैठक संपन्न हुई । इस बैठक में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सुझाव एवं समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई रांची रेल मंडल पर गठित यूनिट के सदस्यों की ओर से सभी उद्यमियों को यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओ का समाधान किया जाएगा तथा रेलवे की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता की जाएगी। बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के समन्वयक वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, सदस्य वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक शांतनु मुखर्जी ने यूनिट के उद्देश्य एवं कार्य की रूपरेखा से उद्यमियों को अवगत कराया। झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कुणाल अजमानी, महासचिव धीरज तनेजा एवं सदस्यों ने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट के गठन को बहुत अच्छी पहल बताया तथा रेलवे का इस बैठक के लिए धन्यवाद दिया। इस बैठक में झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से नवजोत अलंग, झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के भूतपूर्व अध्यक्ष सज्जन सर्राफ, सदस्य श्री अमित शर्मा, श्री रोहित अग्रवाल, श्री मुकेश अग्रवाल, आदित्य मल्होत्रा उपस्थित थे

वनों को उजाड़ कर कोयला खनन क्यों ?

जब जंगलों को उजाड़े बिना देश की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयला भंडार मौजूद हैं, तो जैव-विविधता से भरपूर इस खजाने को क्यों उजाड़ा जाए ?

मोदी सरकार द्वारा 18 जून को देश की 41 कोयला खदानों की नीलामी के ऐलान के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सोरेन ने इससे पहले केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि कोरोना महामारी के वक्त आनन-फानन में घने जंगलों वाले इलाके कोयला खनन के लिए न खोले जाएं. अब झारखंड सरकार ने सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार के इस कदम को चुनौती दी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन और पर्यावरण मंत्री ने भी केंद्र सरकार से कहा है कि वनों और पर्यावरण की सरक्षा और भविष्य में मानव-हाथी द्वंद रोकने के लिए राज्य के हसदेव अरण्य जैसे घने जंगल क्षेत्र में खनन न किया जाए. कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिख कर कहा है कि इस नीलामी को निरस्त किया जाए.

क्या चाहती है केंद्र सरकार?

केंद्र सरकार ने बीते गुरुवार देश के पांच राज्यों की 41 कोयला खदानों की नीलामी का ऐलान किया. ये खदानें कमर्शियल माइनिंग के लिए खोली जा रही हैं. यानी खनन करने वाली निजी कंपनियां भी अब कोयले को खुले बाजार में किसी को भी बेच सकती हैं. कुल 41 में से 29 खदानें तो देश के तीन राज्यों झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही हैं. बाकी तेरह खदानें ओडिशा और महाराष्ट्र में हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस नीलामी के जरिए कोरोना महामारी से पैदा संकट को अवसर में बदला जाएगा. उन्होंने कहा कि कोल माइनिंग से भारत का कोयला आयात घटेगा जिससे विदेशी मुद्रा बचेगी और वह आत्मनिर्भर बनेगा. गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि इस फैसले से 2.8 लाख से अधिक नौकरियां मिलेंगी, 33,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और राज्यों को सालाना 20,000 करोड़ रुपये की कमाई होगी.

घने वन क्षेत्र हो जाएंगे बर्बाद

मोदी सरकार के इस फैसले पर जिन वजहों से सवाल उठे हैं उनमें पहली बड़ी चिंता पर्यावरण का विनाश होने की है क्योंकि जिन जंगलों को नीलामी के लिए खोला जा रहा है वह नदियों, झरनों और जैव विविधता से भरपूर हैं जहां वन्य जीवों की भरमार है. मिसाल के तौर पर छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में चार कोयला खदानें नीलाम हो रही हैं जिनका कुल 87 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल घना जंगल है.

इसी तरह महाराष्ट्र के बंदेर और मध्यप्रदेश के गोटीटोरिया (पूर्व) कोयला खान क्षेत्र 80% जंगलों से ढका है. झारखंड के चकला में 55% जंगल हैं और यह दामोदर और बकरी जैसी नदियों का जलागम क्षेत्र है. जानकार कहते हैं कि यूपीए सरकार के वक्त घने जंगलों में खनन प्रतिबंधित करने की 'गो' और 'नो-गो' कोल एरिया नीति धीरे-धीरे कमजोर होती गई है और इसी कारण अब प्रचुर वन संपदा वाले जंगल खनन के लिए दिए जा रहे हैं। हसदेव अरण्य का यह इलाका न केवल अमूल्य जैव विविधता का भंडार है बल्कि सिंचाई की जरूरत पूरा करने वाली नदियों का जलागम क्षेत्र भी है.

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन से जुड़े पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला कहते हैं कि हसदेव अरण्य में खनन से न केवल अमूल्य वन संपदा खत्म होगी, बल्कि पानी का गंभीर संकट भी पैदा हो जाएगा, "यहां हसदेव नदी पर बांगो बांध बना है जिससे चार लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है. यह क्षेत्र हाथियों का प्राकृतिक बसेरा और कॉरिडोर भी है. साथ ही ये गोंड आदिवासियों का घर है और उनकी आजीविका और संस्कृति इसके साथ जुड़ी है. इसी आधार पर साल 2009 में सरकार ने ही इस इलाके को नो-ग' क्षेत्र घोषित किया था. यह खुद सरकारी दस्तावेजों में कहा

गया है कि अगर हसदेव अरण्य को छोड़ भी दिया जाए तो कोयला उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

जानकार सवाल उठाते हैं कि जब भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है तो फिर वह घने जंगलों को काट कर कोयला कैसे निकाल सकता है. पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इस नीलामी को रोकने की मांग करते हुए कहा, "जैव विविधता से भरे इलाकों में कोल-ब्लॉक्स की नीलामी और 'गो' और 'नो-गो' वर्गीकरण की अनदेखी से तीन-तरफा विनाश होगा. इसे (नीलामी को) तुरंत रद्द किया जाना चाहिए. राजनीतिक रूप से मजबूत बिजली कंपनियों का असर दिख रहा है. प्रधानमंत्री को जलवायु परिवर्तन पर किए वादे को पूरा करना चाहिए." हालांकि प्रधानमंत्री ने कोल ब्लॉक्स की नीलामी के वक्त कहा है कि खनन की इस प्रक्रिया में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

कोयले की जरूरत का गणित

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन ने जहां राज्यों की सहमति के बिना नीलामी को "संघीय भावना का खुला अपमान'' बताया है, वहीं जानकार यह सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या भारत को कोयले के किए ज रूरत पूरा करने के लिए उन जंगलों में घुसने की जरूरत है जहां कोयले की मौजूदगी की पूरी जांच नहीं की गई है. साल 2019-20 में भारत का कुल कोयला उत्पादन 72.1 करोड़ टन रहा और उसने 24.29 करोड़ टन आयात किया गया. यानी उत्पादन और आयात मिलाकर कुल 97.2 करोड़ टन. जबकि इस साल कोयले की कुल खपत 88.71 करोड़ टन रही है. कोयला मंत्रालय के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि देश में अभी कुल 14,800 करोड़ टन का कोयला भंडार (प्रूवन कोल) ऐसा है जिसके लिए नए जंगलों (नो-गो क्षेत्र) को काटने की जरूरत नहीं है. कोल इंडिया की रिपोर्ट "कोल विजन-2030" के मुताबिक साल 2030 तक देश में 150 करोड़ टन कोयले की सालाना जरूरत का अनुमान है. इस हिसाब से अभी उपलब्ध 14,800 करोड़ टन का भंडार तो अगले कई दशकों तक भारत की जरूरतों के पर्याप्त है.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के नंदीकेश शिवलिंगम कहते हैं, "देश में अभी भले ही 600 से अधिक कोल ब्लॉक हैं लेकिन 50 या 60 कोल ब्लॉक ही हैं जहां से अधिकांश कोयला निकाला जाता है. ये सारे बड़े कोल ब्लॉक हैं और इनकी उत्पादन क्षमता अधिक है. बहुत सारी खानें प्रोडक्टिव नहीं हैं. इसलिए हमें सिर्फ जंगलों को खोलने पर ही जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर हम समझदारी के साथ माइनिंग करें, तो अगले कई दशकों तक बहुमूल्य जंगलों को बचा सकते हैं।

साफ ऊर्जा का बढ़ता ग्राफ

घने जंगलों में कमर्शियल कोयला खनन के खिलाफ एक अहम तर्क भारत की साफ ऊर्जा पॉलिसी से जुड़ा है. कोयला बिजलीघर अभी भारत के कुल उत्पादन का करीब 65% पावर देते हैं और आने वाले वक्त में भी कोयले पर भारत की निर्भरता बनी रहेगी लेकिन पिछले एक दशक में देश में साफ ऊर्जा (मुख्य रूप से सोलर पावर) का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. इससे यह सवाल भी उठता है कि आने वाले दिनों में क्या कोल पावर का हिस्सा नहीं घटेगा.

अपनी ताजा रिपोर्ट में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी सीईए ने कहा है कि साल 2030 तक भारत में सोलर पावर जनरेशन, कोल पावर को पीछे छोड़ देगा. अभी साफ ऊर्जा (सौर, पवन, बायोमास, हाइड्रो और न्यूक्लीयर) कुल पावर जनरेशन का करीब 22 प्रतिशत है. सीईए की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यह आंकड़ा 44 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा. दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (टेरी) का अध्ययन बताता है कि 2030 तक सौर ऊर्जा 2.30 से 1.90 रुपये प्रति यूनिट तक सस्ती हो सकती है और इसकी स्टोरेज का खर्च भी 70% घटेगा। जलवायु परिवर्तन पर नजर रखने वाली कंपनी क्लाइमेट ट्रेंड की आरती खोसला कहती हैं, "सोलर पावर लगातार सस्ती हो रही है और कोयला बिजली कंपनियों के लिए कीमतों का कम्पटीशन झेलना मुश्किल हो रहा है. अगर हम इस–ाके साथ कोयला बिजलीघरों से निकलने वाले धुएं का सेहत पर पड़ रहा दुष्प्रभाव जोड़ दें तो साफ नजर आता है कि यह भारत के लिए आने वाले दिनों का रास्ता नहीं है. सरकार को उन स्वस्थ जंगलों को काटने से पहले कई बार सोचना चाहिए जो ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ढाल तैयार करते हैं।

उद्योगों को चाहिए कोयला

यह सच है कि कोयले की जरूरत पावर सेक्टर के अलावा स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और खाद जैसे उद्योगों के लिए भी है और नई खदानों के पीछे यह तर्क है कि इंडस्ट्री को इसके लिए सौर ऊर्जा के बजाय कोयला ही चाहिए औद्योगिक क्षेत्र के जानकार कहते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से अभी उद्योग धंधे भले ही ठंडे पड़े हैं लेकिन जल्द ही इन उद्योगों को कोयला चाहिए होगा। लेकिन स्टील उद्योग में इस्तेमाल होने वाला कोकिंग कोल भारत में बहुत कम पाया जाता है और ज्यादातर कंपनियों को इसे आयात ही करना पड़ता है. सरकार ने इस नीलामी में 4 खदानें कोकिंग कोल की भी रखी हैं लेकिन भारत में कोकिंग कोल की क्वॉलिटी बहुत अच्छी नहीं है. इसके अलावा समुद्र तटीय इलाकों में पावर प्लांट हों या कोई औद्योगिक कारखाना, कई बार उनके लिए देश से कोयला खरीदने के बजाय समुद्री रास्ते से विदेश से कोयला आयात करना सस्ता पड़ता है. यह देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या इस नीलामी में हिस्सा लेने वाली माइनिंग कंपनियां इस तथ्य पर विचार करेंगी. ●

सी.सी.एल. का लालखंटगा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर

संवाददाताः पूरे विश्वी सहित भारत में भी कोविड-19 महामारी का प्रकोप जारी है। ऐसे अवसर में सेंट्रलकोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) के कोरोना योद्धा आज 08 जुलाई को नामकुम ब्लॉक स्थित लालखंटगा गांव में जाकर ग्रामीण बच्चोंा, बुजुर्गों एवं महिलाओं को कोविड -19 से संबंधित अद्यतन जानकारी दिया गया और दवाईयां, मास्को एवं सैनेटाईजर का निःशुल्क वितरित किया गया।

सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह के निर्देशन में चिकित्सा सेवा लॉकडाउन के दौरान भी सीसीएल के चिकित्सशक हेल्प लाईन के माध्यम से आमजनों को कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करते आ रहे हैं। चिकित्साा सेवा के अतिरिक्त खाद्यान सामग्री, सामुदायिक रसोई द्वारा पका हुआ भोजन आदि का भी व्यवस्था जरूरमंदों के लिए किया गया था। शिविर में लगभग 50 ग्रामीणों सहित बच्चों कों निःशुल्क दवा एव ंचिकित्सीय सलाह प्रदान किया गया। इनमें 20 ऐसे बच्चे थे जिनके माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते हैं। साथ ही सीसीएल के चिकित्सकों द्वारा लोगों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु जागरूक किया गया। चिकित्सिक टीम द्वारा बताया गया कि आप किस तरह से सोशल डिस्टेंशिंग, स्वच्छता, सैनेटाईजर, मास्क आदि का प्रयोग कर कोरोना से बच सकते हैं।

शिविर के सफल आयोजन में सीएमओ इंचार्ज जन-आरोग्य केन्द्र, डॉ. अंजना झा, सीएमओ, डॉ ए. हेम्ब्रोम, हरमन खालखो एवं अन्यका महत्व पूर्ण योगदान रहा। ग्रामीणों ने इस स्वास्थ्य शिविर पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त किया और इस आयोजन के लिए सीसीएल को धन्यवाद दिया।

भारी बारिश के बाद नेपाल की नदियों और बराज से छोड़े गये पानी के कारण

बिहार फिर से बाढ़ की चपेट में

राहुल राज

बिहार एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है।राज्य की 25 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित है।राज्य के करीब 12 जिलों के 77 प्रखंडों के 546 पंचायत पानी में डूबे हुए हैं।अब तक बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। सालों से चली आ रही इस समस्या पर सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात जस के तस हैं।

बिहार के कटिहार जिला में कदवा प्रखंड सोनाली पूर्णिया मार्ग को जोड़ने वाली सड़क के बीच करीबन 2 साल से पुल का निर्माण नहीं होने के कारण डायवर्सन के ऊपर से पानी बह रहा है जिससे आवागमन पूरी तरफ से ठप हो गई है । कटिहार के डीएम कवंल तनुज जी के द्वारा सरकारी नाव का चलने का निर्देश दे दिए है

नेपाल में भारी बारिश और बराज से पानी छोड़ने के कारण कोसी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कोसी तटबंध के भीतर रहनेवाले लोगों का कहना है कि जिस तरह कोसी में पानी बढ़ रहा है, कभी भी बाढ़ आ सकती है।

पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। पूर्णिया और अररिया के तो कई हिस्सों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। पिछले साल भी बिहार में बाढ़ ने कोहराम मचाया था। राज्य के 17 जिलों में बाढ़ का पानी घुस गया था। बाढ़ से करीब 1।71 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे।

बाढ़ के कारण 8।5 लाख लोगों के घर टूट गए थे और उत्तर बिहार में 514 लोगों की मौत हो गई थी। बाढ़ के कारण फसलों को भी नुकसान हुआ था। आंकड़ों के अनुसार, करीब 8 लाख एकड़ में लगी खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। वहीं, उत्तर बिहार में 700 किलोमीटर स्टेट हाईवे और डेढ़ दर्जन नेशनल हाईवे बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए थे। रोड बर्बाद होने से करीब 1000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

कांके डैम संरक्षण समिति का कांके डैम बचाओ आंदोलन

रांची संवाददाता : कांके डैम संरक्षण समिति ने कांके डैम बचाओ आंदोलन शुरु किया गई। पहले चरण में कोरोना संक्रमण से बचने की चुनौती और सावधानी के बीच चुनिंदा लोगों की उपस्थिति में डैम के चारों ओर चरणबद्ध पदयात्रा और सत्याग्रह रखा गया है।पहले चरण में डैम के देवी मंडप रोड,हेसल के रास्ते पदयात्रा की गई। इसके बाद लक्ष्मी नगर, पंडरा,इंद्रपूरी,कठल गोंदा, मिशिर गोंदा,मिशन गली,टिकली टोला,हथिया गोंदा,पतरागोंदा तथा सोसो के इलाके में लगातार पदयात्रा और सत्याग्रह जारी रहेगा।

इसके पूर्व 8जुलाई को कांके डैम संरक्षण समिति की बैठक पतरागोंदा में हुई थी । बैठक में कांके डैम समिति से जुड़े दर्जनों गांव के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिसमें,पतरा गोंदा,हथिया गोंदा,मिशिर गोंदा,टिकली टोला,मिशन गली,कठलगोंदा हेसल,करंज टोली,लक्ष्मी नगर,पण्डरा,सोसो आदि गाँव के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। उस बैठक में रमेश मुंडा,मंटू मुंडा,आजू मुंडा,मनोज उरांव , करन मुंडा,सूरज तिर्की,महेन्द्र मुंडा,अंजीत उरांव,बिरसा मुंडा,दशरथ गाड़ी,लक्ष्मण नायक,कर्मा लोहरा,बैजनाथ लोहरा,सुकरा उरांव,पिंटू मुंडा,कृष्णा पाहन,सोनू उरांव आदि शामिल हुए थे। उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पिछले तीन साल से कांके डैम के सीमांकन,कांके डैम को अतिक्रमण मुक्त कर घेराबंदी करने, कांके डैम में नालों माध्यम से रांची शहर का कचरा युक्त गंदे पानी पर रोक लगाने , डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा डैम में मछली पालन कर जीवनयापन करने वाले मछुआरों का आजीविका छीन कर टेंडर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने संबंधित विभिन्न माँगों को लेकर समिति ने कई बार धरना प्रदर्शन तथा अलग अलग स्तर पर पत्राचार किया लेकिन किसी अधिकारी या मंत्री के कान में जूं तक नहीं रेंगा।

अब12जुलाई से अनिश्चित काल के लिए "कांके डैम बचाओ आंदोलन" की शुरुआत किया गया है। यह आंदोलन कांके डैम के पश्चिमी तट के फुटबॉल मैदान(पतरागोंदा) सें शुरू हुआ और तब तक जारी रहेगा जब तक संबंधित विभाग/निगम द्वारा सभी माँगों पर विचार कर किसी ठोस निर्णय और नतीजे तक न पहुँच जाए तथा उस पर क्रियान्वयन शुरू न हो जाए।

सतत कृषि प्रणाली में आम्लीय भूमि प्रबंधन की आवश्यकता

संवाददाता

अम्लीय भूमि एक ऐसी समस्याग्रस्त भूमि है, जिसका सही प्रबंधन कर फसल पैदावार में उचित बढ़ोतरी का प्रयास करने की जरूरत है।जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 5।5 से कम हों, ऐसे भूमि को आम्लीय समस्याग्रस्त भूमि कहा जाता है। इस तरह की मिट्टी में फसल पैदावार एवं उर्वरक की दक्षता बढ़ाने के लिए मिट्टी में आम्लीयता का सुधार चूना तत्व डालकर किया जाता है।

झारखण्ड में आम्लिक भूमि की स्थिति बीएयू में मृदा वैज्ञानिकों के शोध में झारखण्ड प्रदेश की करीब 46 प्रतिशत खेती योग्य भूमि आम्लीय समस्या से ग्रस्त देखा गया है। जहाँ राज्य का क्रमशः पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, रांची, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सरायकेला, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह एवं हजारीबाग जिला की 50 प्रतिशत से अधिक भूमि आम्लीय समस्याग्रस्त पाया गया है। आम्लीय गुणों की वजह से इन जिलों की 40 से 95 प्रतिशत भूमि में उपलब्ध स्फूर की कमी पाई गई है जिससे विभिन्न फसलों की उत्पादकता में प्रतिकूल प्रभाव मिला है।

भूमि आम्लीयता के कारण

अधिक वर्षा के कारण भूमि की उपरी सतह से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम व मैग्नीशियम आदि का पानी में बहाव तथा

जंगली क्षेत्रों में पेड़ों से पत्तियों के गिरने से सड़न से निकले कार्बनिक अम्ल भूमि की आम्लीयता को बढ़ाता है।

आम्लीय भूमि की समस्यायें

ऐसी भूमि में पौधों की जड़ो की सामान्य वृद्धि रूक जाने से जड़े छोटी, मोटी और इकठ्ठी रह जाती है। पौधे अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते है। पौधों को स्फूर व मोलिबडेनम की उपलब्धता कम हो जाती है । मिट्टी में साधारणतया कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाश व बोरोन की कमी देखी जाती है। पौधों के लिए आवश्यक पोषक के असंतुलन से पैदावार में कमी हो जाती है।

सफल खेती में आम्लीय भूमि का प्रबंधन

बीएयू मृदा वैज्ञानिक डॉ अरविन्द कुमार बताते है कि प्रदेश के किसानों के खेतों में किये गये शोध में चूना तत्व के प्रयोग से भूमि की आम्लियता को दूर कर पैदावार में बढ़ोतरी पाई गई है। बीएयू में दशकों से चल रहे शोध में संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक के साथ-साथ चूना तत्व के प्रयोग से 3 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज में बढ़ोतरी की बात सामने आई है।

हाल में आईसीएआर-एनएआईपी परियोजना के तहत 3 वर्षो तक राज्य के दुमका जिले के दुमका व जामा प्रखंड के 18 गाँवो तथा जामताड़ा जिले के जामताड़ा व नारायणपुर प्रखंड के 14 गाँवो के किसानों के खेतों में चूना तत्व के प्रयोग से मक्का + अरहर अंतर फसल प्रणाली प्रत्यक्षण के उत्साहजनक परिणाम परिलक्षित हुए है। इसमें अनुशंसित मात्रा में एनपीके उर्वरक के साथ चूना के प्रयोग से 32।98 प्रतिशत उपज में वृद्धि देखी गई। जहाँ फसल मक्का (अनाज) की तुलना में अरहर की फसल (दालों) में चूना के प्रयोग का प्रभाव अधिक देखा गया।

आम्लीय भूमि सुधारक तत्व

बाजारू चूना के अलावे आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग, डोलोमाइट, प्रेस मड, लाइम शेल व पेपर मिल स्लज आदि का प्रयोग आम्लीय भूमि सुधारक के रूप में किया जा सकता है। इन तत्वो का चूर्ण 80 मेस तक बारीक़ पीसा होना जरूरी है।

बीएयू में किये गये शोध में आम्लीय भूमि सुधारक तत्व के व्यवहार से फसलों की उत्पादकता में बढ़ोतरी तथा मिट्टी के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में सुधार पाया गया है। इन तत्वों में से किसी एक का 2 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष बरसात के मौसम में बुआई के समय पंक्तियों में डालना लाभकारी पाया गया है। आम्लीय भूमि में कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट के साथ चूना तत्व के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को बचाया जा सकता है

कोल इंडिया में हड़ताल अवधि में 58%ओबीआर कोयला कम्पोजिट

कोल इंडिया ने तीन-दिवसीय हड़ताल (2 से 4 जुलाई तक) के दौरान कुल 1.72 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और अपने उपभोक्ताओं को 1.60 मिलियन टन की आपूर्ति किया। विदित हो कि कोल इंडिया एवं अनुषंगी कंपनी में विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा कमर्शियल माईनिंग के विरोध में तीन दिवसीय हड़ताल किया गया था। हड़ताल अवधि के दौरान ओवर बर्डन रिमूवल (ओबीआर) और कोल कम्पोजिट की कुल मात्रा 14.20 मिलियन टन किया गया। ओबीआर और कोल कम्पोजिट का संयुक्त अर्थ है कि खनन स्थान पर भूमि का उपरी सतह हटा कर कोयला खनन के लिए तैयार करना है। खनन कार्य में ओबीआर एक महत्वपूर्ण बिन्दू है जिसके तहत कंपनी का कोयला उत्पादन निर्भर करता है।

कोल इंडिया में हड़ताल के बावजूद कोल कर्मियों ने पिछले 10 दिनों के औसत की तुलना में 44%कोयला उत्पादन किया। कोल इंडिया औसतनप्रतिदिन 1.3 मिलियन टन कोयले का उत्पादन दस दिनों के दौरान किया था। इसी तरह, कोयले की निकासी, दस-दिन के औसत का 38% था, कोल इंडिया की आपूर्ति प्रतिदिन 1.40 मिलियन टन था। ओबीआर एवं कोयला कम्पोजिटका 58% का उच्चतम रिकार्ड पहुंचा और औसत प्रतिदिन का 8.14 मिलियन टन हो गया। कोल इंडिया ने प्रतिदिन औसतन 0.57 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और उसी तीनदिन के दौरान 0.53 मिलियन टन का प्रेषण किया। जबकि, ओबीआर और कोयला कम्पोजिट का औसत प्रतिदिन 4.73 मीलियन टन था। हड़ताल अवधि के दौरान पहले दिन से कर्मचारियों की उपस्थिति निरंतर 36% के करीब बढ़ती गयी, अर्थात कंपनी में उपस्थिति की एक-तिहाई से अधिक के साथ 58% ओबीआर और कोयला कम्पोजिट संयुक्त रूप से उत्पादन किया।

फोटो न्यूज

रिमझिम बारिश , धान रोपाई ने पकड़ी रफ्तार

एनि

लॉकडाउन के असर से इस बार खेतों में अक्सर मानसून के दौरान देखे जाने वाली हरियाली नामुमकिन सी जान पड़ रही थी। पर जैसे-जैसे मानसून जोर पकड़ रहा है, खेतों में धान रोपाई के लिए आवश्यक पानी जमा हो गया है और धान की रोपाई जोर-शोर से सुरु हो गई है । भारी बारिश के चलते किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी , पानी के लिए मोटर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पढ़ रही है। बरसात भी अच्छी हो रही है और जिसके चलते किसानों के चेहरे भी काफी खिले हुये हैं। किसानों का कहना है कि इस समय अच्छी बारिश होने से फसल से होने वाली मुनाफा भी अच्छी होने की उम्मीद है। बारिश भले ही किसानों के लिए अच्छी है लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी भी फसल के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकता है वही किसानों को इसी बात की चिंता भी सता रही है।

दौड़ने के हैं कई जबरदस्त लाभ

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

दौड़ना जो एक अंतरराष्ट्रीय खेल है वही दूसरी तरफ ये एक बहुत ही लाभदायक व्यायाम भी है। जब हम दौड़ते है तो हमारे शरीर से एंडोफिन जैसे रसायन उत्पन्न होते है जिससे तनाव में कमी आती है और आप तरोताज़ा महसूस करते है। दौड़ने से काफी कैलोरी बर्न होता है ,जो वज़न कम करने में सहायक है और आप आपका दिन चुस्ती ओर फुर्ती से भरा होता है। आइये देखते हैं दौड़ने के जबरदस्त लाभ।

- दौड़ना एक सरल व्यायाम है जो हर उम्र के लोगों के लिए है।
- दौड़ने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है जो दिन भर हमे चुस्त रखता है।
- ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेबल को कम करने में सहायक है।
- दौड़ने से हमारा स्टेमिना भी काफी बढ़ता है और एनर्जी लेबल भी बहुत बढ़ता है।
- रक्त प्रवाह बेहतर होता है और रक्तचाप भी कम होता है जो हमारे दिल को मजबूत बनाता है।
- प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है।
- रोजाना दौड़ने से नींद भी बेहतर आती हैं।
- दौड़ने से हड्डियों में घनत्व बढ़ता है जिससे हड्डी मजबूत होती है।
- मधुमेह भी काफी नियंत्रण किया जा सकता है है अगर नियम से दौड़ने का अभ्यास किया जाये।
- दौड़ना अस्थमा के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है इससे फेफड़ों मजबूत बनते है और अस्थमा में काफी राहत मिलती है।
- वज़न कम करने के लिए बेहतरीन व्यायाम है।
- शरीर के निचले हिस्से को काफी मजबूत बनाता है।
- हड्डियों के जोड़े को भी काफी मजबूत बनाता है।

दौड़ने से पहले किन - किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ?

- अच्छे रनिंग के जूते पहने चाहिए।
- दौड़ने से पहले और वार्म- अप करना चाहिए ।

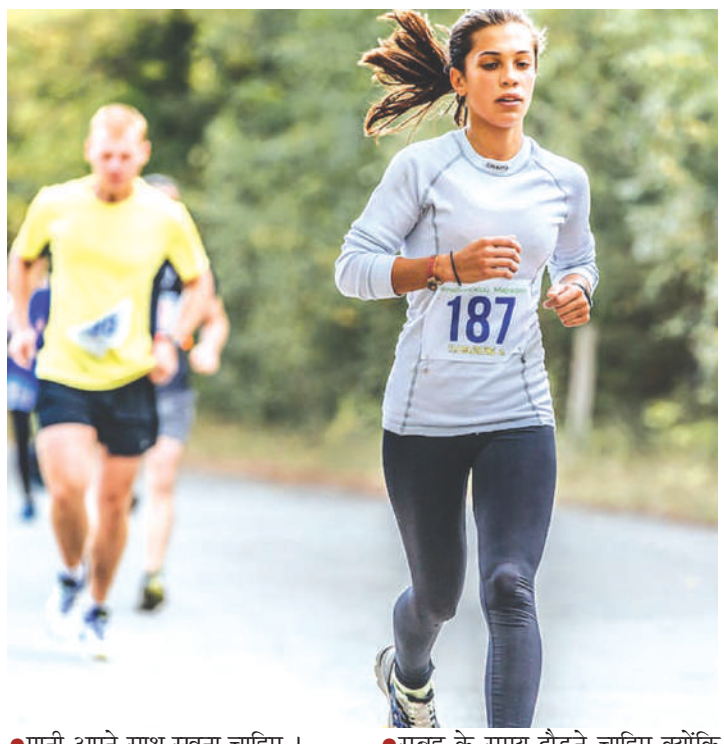

- पानी अपने साथ रखना चाहिए ।
- बहुत ज्यादा सख्त रास्ते पर दौड़ना नहीं चाहिए।
- धीरे- धीरे दौड़ने का समय बढ़ना चाहिए।
- सुबह के समय दौड़ने चाहिए क्योंकि शाम में हवा काफी दूषित होता है।

हमसे जुडे.रहने के लिए (इंस्टाग्राम) instagram पर फ़ॉलो करें ritusinghfitness.

वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी

अवंतिका रॉय

लॉकडाउन के दौरान भले ही लोगों को परेशानी और अर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा हैं लेकिन इससे राज्य में वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी आने से पर्यावरण में काफ़ी अच्छे बदलाव आये हैं। राजधानी रांची की हवा में मौजूद धूलकण (पीएम 10) की मात्रा लॉक-डाउन से पहले मानक सीमा 100 मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर से 40 प्रतिशत तक अधिक करीब 140 तक रिकॉर्ड किया जाता था। लेकिन लॉक-डाउन से प्रदूषण में 43.10 फीसदी की कमी आई। वही लॉकडाउन - 4 में प्रदूषण की कमी 50 फीसदी तक पहुँच गया। इस तरह रांची में ध्वनि प्रदूषण में 24.95 फीसदी तक कमी हुई। प्रदूषण में कमी से पर्यावरण में सुधार हुआ तो बहुत और बदलाव भी दिखे। कई पशु-पक्षी राज्य के विभिन्न शहरों में दिखने लगे। मौसम का मिजाज भी बदला और भी बहुत तरह के परिवर्तन हुए। भविष्य में भी पर्यावरण में सुधार बनाये रखने की और कदम उठाने की जरूरत हैं।

नागवंश की धरोहर है नवरतन गढ़

पूजा

गुमला जिला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे स्थित नवरतन गढ़ किला झारखंड में नागवंश साम्राज्य की कुछ बची हुई धरोहरों में से एक हैं सिसई प्रखंड में स्तिथ इस किले की दूरी रांची से लगभग 75 किलोमीटर है इस किले का निर्माण राजा दुर्जन साल ने 17 वी शताब्दी में करवाया थो इतिहास के पन्नों में इस किले का जिक्र दोसाई गढ़ के नाम से भी किया गया हैं।

घने जंगलों और पहाड़ो से घिरा यह किला मुगल वास्तुकला से प्रेरित थो शुरुआती दौर में यह किला 9 मंजिला थो जिसकी दिवार में अदभुत धर्म, कला और वास्तुशिल्प के चिन्ह उकेरी गई थीं साथ ही साथ दीवारों पर घोड़ा और शेर के आकृति भी बनी हुई हैंकिले के मुख्य द्वार पर बड़ी -बड़ी मूर्तियाँ आज भी देखने को मिलती है किले के अंदर रानी निवास, कचहरी घर, भूलभुलैया, मानसरोवर का भी निर्माण किया गया था। परंतु समय के साथ-साथ संरक्षण और रखरखाव के अभाव में यह किला ढहने लगा है और नौ मंजिला

में से अब तीन मंजिला ही रह गया है । झारखंड बनने के बाद इस किले को सरकार द्वारा अन्य स्थलों के साथ संरक्षण प्रदान करने के लिए सूचिबद्ध कियो लंबे अरसे बाद 2019 में यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आयो जो इस किले की रखरखाव और संरक्षण के लिए बहुत जरूरी थो भारतीय इतिहास , वास्तुकला और प्राकृति में रुचि रखने वालों के लि ये सप्ताहांत में घूमने के लिए एक बहुत ही सुंदर, मोहक, रमणिक जगह हैं।

सारंडा एशिया का संबसे बड़ा साल वृक्ष जंगल

श्यामली कुमारी

पेड़ पौधे, जंगल झाड़ व प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा राज्य झारखंड पर्यावरण का दिया हुआ एक अनूठा वरदान है। झारखंड राज्य का शाब्दिक अर्थ है जंगल झाड़। इस शाब्दिक अर्थ को समझने के लिए राज्य में तमाम उदाहरण भरे पड़े है उन्हीं में से एक है "सारंडा जंगल।"

पश्चिम सिंहभूम के चाईबासा से 70किलोमीटर दूर सारंडा वन झारखंड ओडिशा व छत्तीसगढ़ सीमा क्षेत्र में फैला हुआ है। सारंडा जंगल एशिया की सबसे बड़ी साल वृक्ष की जंगल है। सारंडा जंगल को हाथियों का जंगल भी कहा जाता है। 700 घने पेड़ो, झरने व बड़े पहाड़ों से घिरे सा-रंडा जंगल अपने खूबसूरती व पर्यटकों का मन मोहने के लिए प्रसिद्ध है। सारंडा की पहाड़ियों में से एक "किरीबुरु" में जादुई सूर्योदय व जादुई सूर्यास्त देखने पर्यटक देश विदेश से आते है। किरीबुरु सूर्योदय व सूर्यास्त के नजारा अद्धभुत होता है।

सारंडा के जंगलों में साल वृक्ष के अलावा तमाम तरह के पशु पक्षी, बड़ी संख्या में हाथी और विलुप्त होने के कगार पर पहुँच चुकी उड़ने छिपकली भी देखने को मिलती है। यहाँ के जंगल बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां व अन्य जरूरी पेड़ पौधे का उत्पादक है। बड़ी संख्या में पर्यटक सारंडा के खूबसूरत सुरम्य झरनों को देखने जाते है। झिकरा झरने के लिए वन ट्रेल्स, प्रकृति प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए मनोहरी है। पर्यटक के साथ साथ कई शोधार्थी छात्र किरीबुरु व मेघाहातुबुरु स्थित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लौह अयस्क की खानों के देखने जाते है, ये पूरा क्षेत्र अपने लौह के खान के लिए सुप्रसिद्ध है। एक वक्त पर सारंडा पूरी तरह नक्सलवाद के जद में था लेकिन आज वापस धीरे धीरे सारंडा अपने मूल पहचान की ओर लौट रहा है, झारखंड व अन्य राज्य के पर्यटकों को झारखंड के इस खूबसूरत जंगल का नजारा देखने अवश्य जाना चाहिए।

सारंडा के घने जंगलों को देखने इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि जनजातीय समुदाय का सदियों पुराना संस्कृति आज भी उसी स्वरूप में नैसर्गिक सौंदर्य के साथ जीवित है जिसे जानने समझने व देखने एकबार अवश्य जाना चाहिए।

वर्तमान की जरूरत है इको आर्किटेक्चर

शिल्पी वर्मा

मानव सभ्यता से घरों को बनाने का चलन शुरू हुआ। हड़प्पन और मोहजोदड़ो के नगरों को यदि हम देखते हैं तो यह जानेंगे कि शहरों की अच्छी खासी प्लानिंग की गयी थी। यह प्लानिंग बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से की गयी थी इनमें एक आधुनिक शहर की सा-री व्यवस्थायें की गयी थीं। जैसे चौड़ी सड़-कें दायीं ओर जाकर मिलती थीं और छाटी एवं पतली सड़कें सिर्फ उन्हें आपस में जोड़ती थी और पैदल चलने वालों के लिये थीं।

आज जब हम कोरोना संकट के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे हैं तब हमारे मन में यह विचार आता है कि क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम आगे भी सुरक्षित बच पायेंगे? इस स्थिति से निबटने के लिये और आने वाली की पीढी की सुरक्षा के लिये टिकाऊ और सुरक्षित वास्तु की जरूरत पड़ेगी। इसे हम सस्टेनेबल आर्किटेक्ट कह सकते हैं। आज ग्रीन बिल्डिंग की थ्यौरी पढाई जा रही है। इन बिल्डिंगों में बारिश के पानी को पुनः उपयोग में लाना और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुये पेड़ पौधों से हरा भरा रखना प्रमुखता होती है ताकि उपयोगिता के साथ ही साज सज्जा और उसके भव्यता भी दिखे। इन भवनों में ऐसी तकनीक और

सामग्रियां उपयोग की जाती हैं जो बाद में दुबारा उपयोग में लायी जा सकती हैं। यहां रिन्यूएबल ऊर्जा को भी ध्यान में रखा जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट का टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल होना सबसे पहली शर्त होती है। मिस्त्र के पिरामीड भी इसी आधार पर बनाये गये थे। नाइजीरिया का मकाको फ्लोटिंग यानि कि तैरता हुआ स्कूल इसका बेमिसाल उदाहरण है। यह एक सफल अभिनव प्रयोग है। बांस के फाल्स सीलिंग, बांस की चटाइयां, प्लाइवूड, गर्मी या प्रतिध्वनी रोधक के तौर पर उपयोग किये जा सकते हैं। यह एक आउटडेटेड तरीका लगे पर यह सभी तरीके ऊर्जा को बचाते हैं। ठिक वैसे ही जैसे घर की लीपाई करने से वह साफ भी दिखता और ठंढक भी बरकरार रहती है। जबकि यह एक पुराना और पारंपरिक तरीका है। ऊर्जा , जल और कचड़ा इन तीन चीजों के प्रबंधन मात्र करने भर से ही इको आर्किटेक्चर सफल हो जाता है। इसके लिये हमें स्थानीय और घरेलु सामग्रियों का ही पयोग करना चाहिये। इससे पर्यावरण भी शुद्ध रहता है और ताप वृद्धी भी नहीं होती। आज देश में कई ऐसी संस्थायें हैं जो अब सस्टेनेबल इको आर्किटेक्चर पर काम कर रही हैं। चाहे वो घर हो, आफिस कॉरपोरेट हाउसेस या लक्जरी होटेल अब उनके निर्माण में भविष्य की सुरक्षा, पर्यावरर्णीय पहलुओं को देख कर उसके अनुसार ही उन्हें बनाना चाहिये। अब तो विश्वविद्यालयों में कई प्रकार के इको आर्किटेक्चर कोर्स भी शुरू कर दिये गये हैं। यहां तक कि आश्रम के जैसे रिजोर्ट भी प्रचलन में आ गये हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में अर्टसीप एक सोलर हाउस है जिसमें ऊर्जा तो उत्पन्न होती है पर ताप उत्पन्न नहीं होता। यह ऊर्जा तकनीक किसी सरकारी उपक्रम या विभाग के भरोसे नहीं रहता। इटली का इडेन प्रोजेक्ट इसी अर्टसीप तकनीक से सुचारू रूप से चल रहा है।इन पर्यावरण अनुकूल चीजों में स्थानीय सामग्रियों और तकनीकों की बड़ी भूमिका होती है जैसे गुतरात के कच्छ के रण में मूंगा मिट्टी से बनी ईटें, तिरूवनंतपुरम के टेराकोटा से बनी फर्श इत्यादि। अब समय तेजी से हमें यह संदेश दे रहा है कि भविष्य में हमें सब कुछ पर्यावरण अनुकूल ही करना होगा और इको आर्किटेक्चर इसी का उदाहरण है।

आकाशीय बिजली गिरने के हैं बड़े खतरे

डॉ. टीवी वेंकटेश्वरन

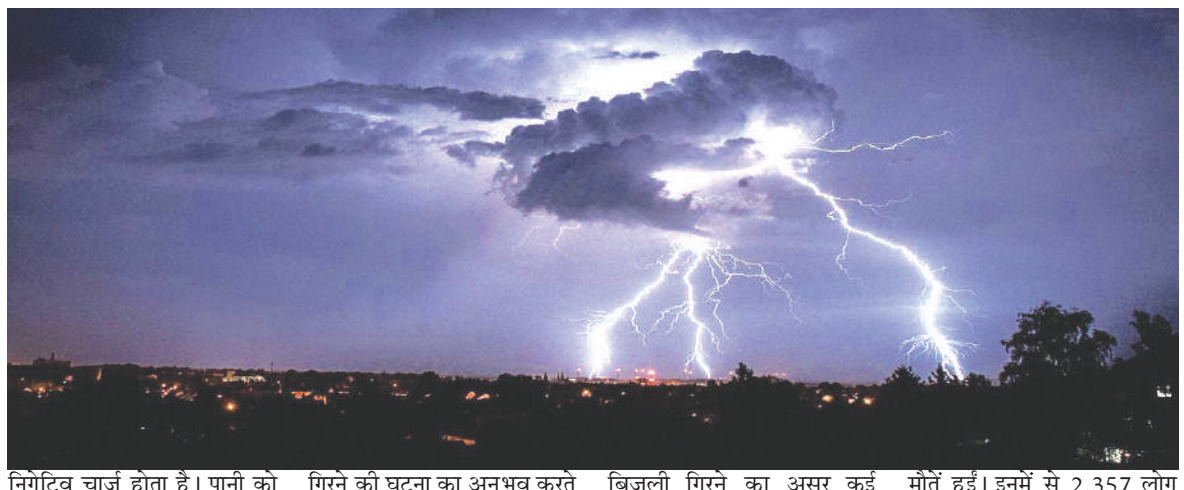

देश में बिजली गिरने से सालाना औसतन 2,500 मौतें होती हैं और वर्ष 1967 से 2018 तक प्राकृतिक आपदाओं में हुई मृत्यु में बिजली गिरने से हुई मौत की हिस्सेदारी 39 प्रतिशत रही है। तिरुवनंतपुरम स्थित नेशनल सेंटर्स फॉर अर्थ साइंस स्टडीज (एनसीईएसएस) ने बिजली गिरने की पूर्वसूचना देने और लोगों के लिए पहले से चेतावनी जारी करने के लिए देश की छह जगहों में लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क स्थापित किया।

मौसम विभाग ने पिछले साल से बिजली गिरने और आंधी-तूफान की पूर्व चेतावनी देनी शुरू की है। इसके अलावा 2018 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी ने इससे संबंधित एक विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किया। वैसे तो सभ्यता की शुरुआत से ही बिजली गिरने की घटनाएं देखी गई हैं, लेकिन बादल किस तरह गर्म हो जाते हैं, इसे अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। जो हम समझ पाए हैं, वह यह है कि आंधी-तूफान की स्थिति में बादलों के ऊपरी सिरे में पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि निचले हिस्से में निगेटिव चार्ज होता है। पानी को बूंदों को अपने में समाई नीचे की गर्म हवा जब बर्फ से भरे ठंडे बादलों से टकराती है, तब आंधी-तूफान की शुरुआत होती है। इस प्रक्रिया में पानी की बूंदों और बर्फ के टुकड़ों के बीच लगातार घर्षण होता है। जब आकाश का गर्म क्षेत्र अचानक खुद को डिस्चार्ज करता है, तब बिजली गिरने की घटना होती है। यह घटना बादलों के दो क्षेत्रों या दो बादलों के बीच होती है। जब यह डिस्चार्ज बादलों के दो क्षेत्रों के बीच होता है, तब हम एक जगह और देर तक बिजली गिरने की घटना का अनुभव करते हैं।पर जब यह डिस्चार्ज दो बादलों के बीच होता है, तब हम रोशनी को एक से दूसरी जगह जाते देखते हैं। जब ऐसी घटना बादलों के निचले हिस्से और जमीन के बीच होती है, तब हम उसे बिजली गिरना कहते हैं। बादलों के भीतर और बाहर बिजली चमकने की घटना से जहां विमानों को नुकसान पहुंच सकता है, वहीं बादलों के निचले हिस्से और जमीन के बीच बिजली चमकने से ही, जिसे हम बिजली गिरना कहते हैं, जान-माल का नुकसान होता है। बिजली गिरने का असर कई किलोमीटर तक हो सकता है। इस-की गति काफी तेज लगभग 1,50,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और यह अपने आसपास के वायुमंडल को काफी गर्म कर देता है। पृथ्वी पर बिजली गिरने की घटना प्रति सेकंड में पचास से सौ बार होती है। हर साल 20,000 से अधिक लोग बिजली गिरने से सीधे प्रभावित होते हैं और कई हजार लोगों की इससे मौत हो जाती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक, वर्ष 2018 में प्राकृतिक दुर्योगों से करीब 6,891 मौतें हुईं। इनमें से 2,357 लोग बिजली गिरने से मारे गए, जो प्र-ाकृतिक दुर्योगों से हुई मौतों का 34.2 फीसदी थी। आकाशीय बिजली का गिरना बिजली आपूर्ति ठप कर सकता है, इससे जंगल में आग लग सकती है और कच्चे घरों को नुकसान पहुंच सकता है।

भारत में आकाशीय बिजली के ज्यादातर शिकार खेतों में काम करने वाले ग्रामीण होते हैं। गंदा पानी बिजली का सुचालक होता है। इसलिए पानी से भरे खेतों में लोग अक्सर आकाशीय बिजली के शिकार होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी, पुणे का एक अध्ययन बताता है कि 2004 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में आकाशीय बिजली गिरने से मारे गए लोगों का 86 फीसदी अपने खेतों में काम कर रहे किसान थे।

यही आकाशीय बिजली गिरने का मौसम है। इससे बचने का मुख्य सुरक्षा नियम 30/30 है। यानी बिजली चमकने पर 30 तक गिनने से पहले ही बादल के गरजने पर घर के अंदर चले जाना चाहिए और आखिरी बार बादल गरजने के 30 मिनट तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। खेत में होने पर दोनों पैरों को एक साथ कर सिर झुकाकर बैठ जाना चाहिए। लेटने पर खतरा बढ़ जाता है। खेत में सूखी जमीन में जाना चाहिए। रबर सोल के जूते और रबर के टायर आकाशीय बिजली से सुरक्षा नहीं देते। पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। साइकिल, ट्रैक्टर और धातु से बने कृषि उपकरणों से दूर रहना चाहिए। और घर के अंदर बिजली के उपकरणों के प्लग निकाल देने चाहिए। इन उपायों को अपनाकर आकाशीय बिजली से बचा जा सकता है। ●

(लेखक एक वैज्ञानिक हैं)

वर्चुअल लर्निंग की बढ़ती प्रासंगिकता

सौरभ कुमार मुंडा

साल 2020 का आधा समय निकल निकल चुका है। बीते छः महीनों में हमने अपनी आसपास की दुनिया को जिस तरह से बदलते देखा है, शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। जबसे इस कोरोना महामारी ने समूचे विश्व को अपने चपेट में लिया है, सारे जहां में उथल-पुथल मच गई है। कोई भी क्षेत्र इसके दंश से बच नहीं पाया है। चाहे बात स्वास्थ्य जगत की हो, रोजगार की हो, अर्थव्यवस्था की हो, खेल जगत की हो या शिक्षा की हो। इस महामारी के प्रकोप से हम सब की दैनिक जीवन तो प्रभावित हुई ही है पर इसने शिक्षा जगत में गहरी चोट पहुंचाई है। सभी स्कूल कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट और अन्य शिक्षण संस्थान बंद है। किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण केन्द्र नही खुले हैं। कुल मिलाकर यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पठन-पाठन का पूरा कार्य बाधित हो चुका है। पर ऐसे कठिन दौर में वर्चुअल लर्निंग संजीवनी बूटी साबित हो रहा है। मौजूदा समय में वर्चुअल लर्निंग उन टर्मिनोलॉजी में से एक है जो इस लॉकडाउन में सबके जुबान चढ़ कर बोल रहा है।

आइए जानते हैं क्या होता है वर्चुअल लर्निंग? वर्चुअल लर्निंग दरअसल एक ऐसी लर्निंग प्रोसेस है जिसमें आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी सीख सकते हैं और इसके लिए ना आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत है ना ही किसी तरह के शुल्क देने की आवश्यकता है (कुछ विशेष कार्यक्रमों को छोड़कर) ।वास्तव में वर्चुअल लर्निंग एक वेब आधारित प्लेटफार्म है जो किसी भी तरह के कोर्स या विषयवस्तु का डिजिटल संस्करण होता है जिसमें संबंधित जानकारी या सूचना हम इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल या लैपटॉप में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सूचना या जानकारी के लिए संबंधित विषय के इंस्ट्रक्टर की लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं या फिर अपने फुर्सत के समय में उन सेशनों को कभी भी उनके यूट्यूब चैनल या अधिकारिक ऐप पर देख सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत से स्कूल कॉलेजों ने ऑनलाइन क्लासेज की शुरुआत की है जो कि एक सराहनीय पहल है। वर्चुअल क्लास में एक साथ कई विद्यार्थी अपने शिक्षक या इंस्ट्रक्टर से एक साथ लाइव जुड़ सकते हैं तथा बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव सेशन के अपने फायदे हैं। इसमें आप अपने इंस्ट्रक्टर से जुड़कर सीधे सवाल जवाब कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के डाउट को क्लियर कर सकते हैं।

सिर्फ शिक्षा जगत तक ही नहीं सीमित है वर्चुअल लर्निंग: इंटरनेट के इस युग में वर्चुअल लर्निंग ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। वर्चुअल लर्निंग अब पठन-पाठन तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसने हमारे दैनिक जीवन के सभी आयामों को छुआ है। आप यूट्यूब पर अपनी रुचि के किसी भी विषय की जानकारी और प्रशिक्षण ले सकते हैं। चाहे बात स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की हो या किसी कला में दक्षता हासिल करने की। आपको चाहिए बस एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन। अपने मोबाइल पर अंगुलियां घुमाइए और लेसन आपके स्क्रीन पर हाजिर। ये है वर्चुअल लर्निंग की दुनिया।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।